

• 'हिन्दू विश्व' में प्रकाशित सामग्री लेखकों के निजी विचार हैं। सम्पादक एवं प्रकाशक का उनसे सहमत होना आवश्यक नहीं है।

• 'हिन्दू विश्व' से सम्बन्धित सभी वाद प्रकाशन तिथि से 3 महीने के अन्दर केवल नई दिल्ली स्थित न्यायालय में होंगे।

विदेशों के लिए\$ 50 USD

वार्षिक डाक व्यय सहित

एक प्रति10 ₹

वार्षिक200 ₹

त्रिवर्षीय500 ₹

पंचवर्षीय800 ₹

दसवर्षीय1,500 ₹

पन्द्रहवर्षीय2,100 ₹

गुणवान पुरुषों को भी अपने स्वरूप का ज्ञान दूसरे के द्वारा ही होता है।
आंख अपनी सुन्दरता का दर्शन दर्पण में ही कर सकती है। - वासवदत्ता

अखिल भारतीय सेवा प्रशिक्षण शिविर

19



सम्पादकीय

चर्च की धौंसपट्टी!.....	04
दलित ईसाइयों-बदतर स्तर के लिए जिम्मेवार कौन?.....	05
हिन्दू पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को उठा ले गए थे रोहिंग्या आतंकी.....	07
मेजर गोगोई पर कोई मुकद्मा नहीं.....	08
कश्मीर : दोहरे मापदंड कब तक?.....	09
पत्थर गद्दी.....	10
हिन्दू संस्कृति में रचा-बसा मुस्लिम बहुल इण्डोनेशिया.....	12
क्या मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फोटो छपी है? हां, यह सच है.....	13
शौर्य प्रशिक्षण वर्ग.....	14
बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण.....	15
परिषद शिक्षा वर्ग.....	16
सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी.....	17
एकल की अनूठी पहल.....	19
'क्या देश के सभी स्कूलों में 'वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड' संभव'?.....	21
दानवीरों में श्रेष्ठ भामाशाह.....	22
झील किनारे धर्मांतरण करा रहे थे पादरी; अचानक मगरमच्छ निकला और.....	23
वेटिकन की कठपुतली सरकारें लाने को षडयंत्र रच रहा है चर्च : विहिप.....	24
राम मंदिर को लेकर अभी कोई कानून न बनाए सरकार.....	24
डेनमार्क ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्के और नकाब पहनने पर लगाया प्रतिबन्ध.....	25
यूरोपीय जर्नल ने माना आयुर्वेद का लोहा.....	26



खुला पाताल लोक का रहस्य खुदाई में मिला पूरा शहर और हनुमान जी की मूर्ति

पाताल लोक, वो दुनिया जो जमीन के नीचे है। वो दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना संभव नहीं। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार-बार मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाताल लोक वाकई में है या सिर्फ कल्पना? पाताल लोक के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता। पाताल लोक, वो दुनिया जो जमीन के नीचे है। वो दुनिया जहां इंसानों का पहुंचना संभव नहीं। पौराणिक कथाओं में पाताल लोक का जिक्र बार-बार मिलता है, लेकिन सवाल ये है कि क्या पाताल लोक वाकई में है या सिर्फ कल्पना? पाताल लोक के अस्तित्व को पूरी तरह से नहीं नकारा जा सकता।

रामायण की कथा के मुताबिक पवनपुत्र हनुमान पाताल लोक तक पहुंचे थे। रामायण की कथा के मुताबिक रामभक्त हनुमान अपने ईष्ट देव को अहिरावण के चंगुल से बचाने के लिए एक सुरंग से पाताल लोक पहुंचे थे।

इस कथा के मुताबिक पाताल लोक ठीक धरती के नीचे है। वहां तक पहुंचने के लिए 70 हजार योजन (लगभग 9 लाख 10 हजार कि.मी.) की गहराई पर जाना पड़ेगा। अगर आज के वक्त में हम



अपने देश में कहीं सुरंग खोदना तो जमीन की सीध में ये सुरंग अमेरिका महाद्वीप के मैक्सिको, ब्राजील और होंडुरास जैसे देशों तक पहुंचेगी।

हाल ही में वैज्ञानिकों ने मध्य अमेरिका महाद्वीप के होंडुरास में सैकड़ों वर्ष पहले गुम हो चुके सियूदाद ब्लांका नाम के एक प्राचीन शहर की खोज की है। वैज्ञानिकों ने इस शहर को आधुनिक लाइडर तकनीक से खोज निकाला है।

इस शहर को बहुत से जानकार वो पाताल लोक मान रहे हैं जहां राम भक्त हनुमान पहुंचे थे। दरअसल, इस विश्वास की कई पुख्ता सबूत हैं। संभव है कि भारत या श्रीलंका से कोई सुरंग खोदी जाएगी तो वो सीधे यहीं निकलेगी। दूसरी वजह ये है कि वक्त की हजारों साल पुरानी परतों में दफन सियूदाद ब्लांका में ठीक राम भक्त हनुमान के जैसे वानर देवता की मूर्तियां मिली हैं।

होंडुरास के गुप्त प्राचीन शहर के बारे में सबसे पहले ध्यान दिलाने वाले अमेरिकी खोजी थियोडोर मोर्डे ने दावा किया था कि स्थानीय लोग (वहां के प्राचीन लोग) वानर देवता की ही पूजा करते थे। उस वानर देवता की कहानी काफी हद तक मकरध्वज की कथा से मिलती-जुलती है। हालांकि अभी तक प्राचीन शहर सियूदाद ब्लांका और रामकथा में कोई सीधा रिश्ता नहीं मिला है।

विस्तृत वर्गीकरण के मुताबिक तो 14 लोक हैं—7 तो पृथ्वी से शुरू करते हुए ऊपर और 7 नीचे ये हैं— भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक, महर्लोक, जनलोक, तपोलोक और ब्रह्मलोक। इसी तरह नीचे

वाले लोक हैं— अतल, वितल, सतल, रसातल, तलातल, महातल और पाताल।

आपने धरती पर ऐसे कई स्थानों को देखा या उनके बारे में सुना होगा जिनके नाम के आगे पाताल लगा हुआ है, जैसे पातालकोट, पातालपानी, पातालद्वार, पाताल भैरवी, पाताल दुर्ग, देवलोक पाताल भुवनेश्वर आदि, ये भी पाताल के अस्तित्व पर मुहर लगाते हैं।

क्रमशः



मानवेन्द्र नाथ पंकज

चर्च की धाँसपट्टी!

मिजोरम के नवनियुक्त राज्यपाल के0 राजशेखरन की नियुक्ति के विरुद्ध हंगामा बरपा करते हुए (न्यू इण्डियन एक्सप्रेस के अनुसार) मिजोरम के PRISM अध्यक्ष वनलाल रूआता ने कहा कि हम एक क्रिश्चियन स्टेट हैं। वे आरएसएस के सक्रिय कार्यकर्ता रह चुके हैं। इस साल के आखिर में मिजोरम में चुनाव होने हैं, हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि भाजपा ने इसीलिए उनकी नियुक्ति की है। अगर वह वहां होंगे तो भाजपा उनका इस्तेमाल करेगी।

PRISM ने चर्चों से अपील की है कि वे इस कट्टर हिंदू नेता को बाहर करें। इस हेतु उसने चर्च, पार्टियों व एनजीओ को पत्र लिखा है। मिजोरम में दो संगठन ग्लोबल काउंसिल ऑफ इंडियन क्रिश्चियंस और पीपुल्स रिप्रजेंटेशन फॉर आइडेंटिटी एंड स्टेटस ऑफ मिजोरम (PRISM) नाम के संगठन ने इसके खिलाफ बाकायदा आंदोलन छेड़ दिया है। PRISM की मिजोरम में शुरुआत एक एनजीओ के रूप में हुई थी। 2017 में इसने राजनीतिक दल की शकल ले ली। अब ये संगठन मिजोरम के नए राज्यपाल की नियुक्ति का इसलिए विरोध कर रहा है, क्योंकि वे राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक रह चुके हैं।

ज्ञात हो ईसाईबहुल उ0पू0 राज्य मेघालय की राजधानी शिलांग में सिखों की बस्ती हटाने के लिए दंगे जारी हैं। 150 साल पहले सफाईकर्मियों के रूप में शिलांग में बसाए गए दलित सिखों के लिए संविधान खतरे में है का कोरस क्यों नहीं गाया जा रहा है? ये भी तो अल्पसंख्यक हैं। दुर्भाग्यजनक है कि इन दलित सिखों को वहां से हटाने पर एनडीए की राज्य सरकार सहमत हो गई बताई जा रही है।

इससे पूर्व कैथोलिक बिशप्स कांफ्रेंस ऑफ इण्डिया (सीबीसीआई) के प्रमुख कार्डिनल ओवसाल ग्रेसिम्स ने भी देश के हालात को चिंताजनक करार दिया था। दिल्ली के आर्कबिशप द्वारा देश के हालात को अशांत करार देकर मोदी को हटाने की अपील के बाद गोवा के आर्कबिशप ने संविधान को खतरे में बताकर कहा कि विकास के नाम मानवाधिकार कुचला जा रहा है। अल्पसंख्यकों से जमीनें छीनी जा रही हैं। उन्होंने कैथोलिक्स से राजनीति में सक्रियता निभाने की बात की।

गुजरात विधानसभा चुनाव के समय भी वहां के आर्कबिशप ने भाजपा को हराने की अपील की थी। यह भी ध्यान रहे कि विगत दिल्ली विधानसभा चुनाव के समय चर्च पर हमले का भ्रामक प्रचार कर वैश्विक जगत में कोहराम मचाया गया। भाजपा विधानसभा चुनाव बुरी तरह से हारी। बाद में जांच से पता चला कि चर्च में हमले का कोरस झूठा था। कुछ पैसों की चोरी एक क्रिश्चियन द्वारा ही की गई, ऐसा बताया गया। परन्तु न तो चर्च, न ही सेक्युलरिस्ट कॉकस, न ही प्रायोजित खबरें देने वाले मीडिया ने माफी मांगी।

आज का परिदृश्य बताता है कि 'संविधान खतरे में है, मानवाधिकार कुचला जा रहा है, संघ के लोगों की हर जगह नियुक्तियों की जा रही हैं' का कोरस प्रथम परिवार, सेक्युलरिस्ट कॉकस, कट्टर मुस्लिम व अब आर्कबिशप द्वारा गाया जा रहा है तो संविधान खतरे में है या संविधान की आड़ में धर्मान्तरण की मनमानी छूट, हिंदुओं को पदाक्रांत करने का उन्हें लाइसेंस चाहिए।

चर्च संगठन भूल गये हैं कि सोलहवीं सदी में समुद्री..... फ्रांसिस जेवियर जब गोवा पहुंचा, उसके बाद संत बनकर गोवा में हिंदुओं विशेषतः ब्राह्मणों/पुजारियों का भयानक कत्लेआम किया जो अनेक दशकों तक चालू रहा, हिंदुओं को पूजा- पाठ, भगवान, मंदिरों, मूर्तियों से जबरिया पृथक किया गया। जहां- जहां इनकी संख्या

दलित ईसाइयों-बदतर स्तर के लिए जिम्मेवार कौन?



बलबीर पुंज

क्या मतांतरण के बाद दलितों को सम्मान और न्याय मिल पाया है? यदि वर्तमान समय में दलितों की स्थिति संतोषजनक नहीं है, तो क्या भारतीय उपमहाद्वीप में इस्लाम या ईसाई मत उन्हें सामाजिक न्याय दिला सकता है? यह प्रश्न केरल की उस घटना से जनित है, जिसमें गत दिनों एक दलित-ईसाई केविन पी. जोसेफ की निर्मम हत्या केवल इसलिए कर दी गई, क्योंकि उसने ईसाई मत की एक उच्च जाति की युवती से प्रेम विवाह करने का "दुस्साहस" किया था।

वामपंथी दशकों से और आज भी दलित-मुस्लिम गठजोड़ की वकालत कर रहे हैं। चर्च भी दलितों को मतांतरण के बाद एक आदर्श और संपन्न समाज का स्वप्न दिखाता है। स्वाधीनता पूर्व से दलित इस प्रोपेगंडा का शिकार होते रहे हैं। वामपंथियों के समर्थन से मुस्लिम

लीग ने इसी कुत्सित गठबंधन में बंगाल के दलित नेता जोगेंद्रनाथ मंडल को शामिल किया था, जो पाकिस्तानी संविधान सभा के अध्यक्ष और बाद में वहां की पहली सरकार में मंत्री भी बनाए गए।

मंडल को "दलित-मुस्लिम भाई-भाई" नारे का भयावह रूप तब दिखा, जब मुस्लिम लीग अपने मजहबी एजेंडे के अंतर्गत पाकिस्तान को काफिरों से मुक्त करने में जुट गया। पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान में दलितों सहित अधिकतर गैर-मुस्लिमों ने इस्लामी कट्टरपंथियों का भयंकर उत्पीड़न झेला। अपने समुदाय की रक्षा करने में असमर्थ रहे मंडल, अक्टूबर 1950 को पाकिस्तान की तत्कालीन लियाकत सरकार से त्यागपत्र देकर भारत लौट आए।

ताजा मामला केरल के कोट्टायम से संबंधित है। दो वर्षों के प्रेम-प्रसंग के बाद केविन ने 25 मई को अपनी 20 वर्षीय प्रेमिका नीनु चाको से एडुमनूर स्थित सब-रजिस्ट्रार कार्यालय में शादी कर ली। इसे लेकर युवती के परिजनों ने

थाने में शिकायत भी दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने नीनु को जबरन उसके माता-पिता के पास भेजने की कोशिश भी की, किंतु वह नहीं गई।

27 मई (रविवार) की सुबह तीन वाहनों में सवार होकर हथियारों से लैस कुछ बदमाश आए और उन्होंने मारपीट के बाद केविन और उसके चचेरे भाई अनिश का अपहरण कर लिया। जब परिजन शिकायत करने स्थानीय पुलिस थाने पहुंचे, तब सहायक-अधीक्षक ने मुख्यमंत्री के दौरे में व्यस्त होने की बात कहकर मदद करने से इनकार कर दिया। अनिश को उन लोगों ने छोड़ दिया, किंतु 28 मई को कोल्लम के एक नहर से केविन का शव क्षत-विक्षत स्थिति में मिला।

हत्या का मामला सामने आने के बाद पुलिस-प्रशासन ने शिकायत दर्ज नहीं करने वाले आरोपी सहायक-अधीक्षक को निलंबित कर अपहरण और हत्या के आरोप में दर्जन भर लोगों को नामजद कर लिया। मामले में युवती के पिता-भाई के अतिरिक्त जिन तीन लोगों-नियाज, रियाज और इशान को गिरफ्तार किया गया है, वह सभी वामपंथी छात्र संगठन डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के सक्रिय कार्यकर्ता हैं।

यह सच है कि यदि पुलिस लापरवाही नहीं दिखाती, तो केविन आज

ज्यादा हो रही है, वहां से हिंदू, सिख, चकमा, रियांग को बाहर होना पड़ रहा है। (कृपया देखें-<http://www.kranti doot.in,2017/05/portuguese-christion-werak-havoc-on-the-hindusof-go-a-in-the-sixteece ntury. html.?m-1>)

ये मिशनरीज चीन, श्रीलंका पाकिस्तान में धर्मान्तरण की आजादी के लिए कोहराम क्यों नहीं मचाते, इसका उत्तर केन्द्र सरकार व राज्य सरकारों को खोजना चाहिए।

इन संगठनों की हिमाकत तो देखिए मिजोरम को क्रिश्चियन स्टेट कह रहे हैं। सेक्युलरिज्म के झंडाबरदारों को तो जैसे सांप सूंघ गया है। मिजोरम में राजशेखरन की शपथ लेने से पहले ही माहौल खराब

किया जा रहा है। यह वही मिजोरम है जहां तत्कालीन कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चर्च/बाइबिल के अनुसार शासन चलाने का चुनावी वायदा किया था। यहां चुनाव प्रचार/मतदान चर्च की आचार संहिता से होता है, ऐसे आरोप लगाए जाते रहे हैं। कैसी विडम्बना है कि 40,000 रियांग हिंदुओं को स्वधर्म पर डटे रहने के कारण मिजोरम से भगाया गया, आज वहां हिंदू राज्यपाल होने से क्रिश्चियन स्टेट पर खतरे की आशंका मंडराने लगी।

क्रिश्चियन स्टेट की बात कहना भारत की सम्प्रभुता/संविधान का खुल्लमखुल्ला अपमान है। विचारणीय है कि क्रिश्चियन धार्मिक नेता एक के बाद एक क्यों केन्द्र की

भाजपा सरकार पर हमलावर हो रहे हैं। ये स्वतः तो ऐसा कर नहीं सकते तो क्या वेटिकन ने भारत सरकार को धूलधूसरित करने की मोर्चाबंदी कर ली है? आज आवश्यकता है कि भ्रामक माहौल को छिन्न-भिन्न किया जाए। यह छद्म सेक्युलर बनाम कार्बन कॉपी आफ सेक्युलरिज्म से संभव नहीं दिखता। यह तो प्रचंड हिंदू जागरण से ही संभव है।

आइए! असत्य के मकड़जाल के विरुद्ध सत्य की विजय पताका लेकर गर्वोन्नत हिंदू भाव से आगे बढ़ें!

आने-3 115 4000

(8 जून)

जीवित हो सकता था। किंतु इस घटनाक्रम को केवल पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता का परिणाम बताना और पूरे मामले को उसी चश्मे से देखना—क्या उचित है? जब भी भारत में दलितों पर अत्याचार की घटना सामने आती है, विकृत तर्क—कुतर्कों की झड़ी लगा दी जाती है। क्या केविन हत्या मामले पर निष्पक्ष चर्चा की आवश्यकता नहीं?

दलित—ईसाई केविन की नृशंस हत्या ने चर्च और ईसाई मिशनरियों के उस खोखले दावे व मतांतरण के बाद की सच्चाई को उजागर किया है, जिसमें वह देश के शोषित वर्गों, विशेषकर दलितों को छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का भरोसा देकर संपन्न समाज का स्वप्न दिखाकर

तक सीमित है। मृतक के परिजनों को ना करोड़ों की वित्तीय और आवासीय सहायता मिली है और ना ही किसी सदस्य को नौकरी का प्रस्ताव।

केविन हत्याकांड पर देश में इस उपरोक्त परिदृश्य के चार प्रमुख कारण हैं। पहला—घटनाक्रम में शामिल दोनों परिवार घोषित रूप से गैर—हिंदू है। दूसरा—दलित—ईसाई केविन की हत्या करने वाले अधिकतर वामपंथी छात्र ईसाई के सक्रिय नेता/कार्यकर्ता हैं, जिनकी विचारधारा का मूल ही हिंसा है। तीसरा—जिस राज्य में केविन की हत्या हुई, वहां भाजपा की सरकार नहीं है। चौथा और सबसे महत्वपूर्ण—चर्च की भूमिका।

दिसंबर 2016 को कैथलिक बिशप

दलित—ईसाई केविन की नृशंस हत्या ने चर्च और ईसाई मिशनरियों के उस खोखले दावे व मतांतरण के बाद की सच्चाई को उजागर किया है, जिसमें वह देश के शोषित वर्गों, विशेषकर दलितों को छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का भरोसा देकर संपन्न समाज का स्वप्न दिखाकर छल, भय और प्रलोभन के माध्यम से मतांतरण के लिए प्रेरित करते हैं।

छल, भय और प्रलोभन के माध्यम से मतांतरण के लिए प्रेरित करते हैं। निसंदेह, देश में होने वाला प्रत्येक दलित (पिछड़ों सहित) उत्पीड़न और शोषण—भारतीय समाज के लिए कलंक है। सदियों से हिंदू आध्यात्मिक और राजनीतिक नेतृत्व ने इस सामाजिक अन्याय के विरुद्ध जो तप किया है, वह अभी अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंचा है। इसलिए इस दिशा में अभी काफी कुछ करना शेष है।

मई 2014 के बाद जिन गिने-चुने दलित—अत्याचारों को लेकर देश के स्वघोषित सेकुलरिस्ट, वामपंथी और तथाकथित उदारवादियों—प्रगतिशीलवादियों ने अपनी छाती पीटकर और भारत को कलित कर भाजपा—संघ की दलित विरोधी छवि बनाने की कोशिश है—उसी विकृत समाज की केविन हत्याकांड पर कैसी प्रतिक्रिया है? देश में शांति है। असहिष्णुता नाम की कोई चीज नहीं है। आंदोलन नहीं हो रहा है। बुद्धिजीवी पुरस्कार नहीं लौटा रहे हैं। अधिकतर समाचारपत्र और न्यूज चैनल खबर देने

कांफ्रेंस ऑफ इंडिया (सीबीसीआई) के नीति—पत्र में स्वीकार किया गया है कि चर्च में दलित—ईसाइयों से छुआछूत और भेदभाव बढ़े स्तर पर मौजूद है। केरल में दलित ईसाई को उच्च ईसाई जातियों, विशेषकर सीरियाई ईसाई समाज में शादी करने की अनुमति नहीं है। दलित ईसाइयों का सीरियाई चर्च और कब्रिस्तान में प्रवेश वर्जित है। उनके लिए केरल और अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में अलग से व्यवस्था की गई है। आखिर ईसाई समाज में व्याप्त इस कटु सत्य रूपी जातिभेद को स्वीकार करने में देश के तथाकथित सेकुलर क्यों हिचकते हैं?

भारत में ईसाई मत का इतिहास बहुत पुराना है। ईसा मसीह के देहांत के दो दशक बाद ही सेंट थॉमस केरल के तट पर पहुंचे, जिसके बाद कालांतर में स्थानीय लोगों ने ईसाई मत को अंगीकार किया। वे सभी सीरियाई चर्च को मानने वाले थे। कई शताब्दियों तक वह सभी अन्य मत—मतांतरों के साथ शांति और भाईचारे के वातावरण में रहे। समस्या तब पैदा हुई, जब क्रूसेड के नाम पर पुर्तगाली, डच और अंग्रेज भारतीय

तटों पर उतरे और उनके साथ रोमन कैथोलिक चर्च का भी आगमन हुआ। पुर्तगालियों को यहां ईसाई मत का तत्कालीन स्वरूप, जो किसी तरह से यूरोप से संचालित नहीं था और न ही वहां के रीति—रिवाजों को मानता था—बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने साम, दाम, दंड, भेद के साथ लोगों को ईसा के चरणों में शरण लेने के लिए बाध्य किया, जिसके बाद भारत में कैथोलिक ईसाइयत का विस्तार होने लगा।

क्या भारत में ईसाइयत अपनाने वाले दलितों की स्थिति सुधरी है? दलित ईसाइयों की हालत आज उन दलित जातियों से भी अत्यधिक दयनीय है, जो चुनौतियों से संघर्ष का मार्ग स्वीकार कर आगे बढ़ने लिए प्रयासरत हैं। विदेशी धनबल और स्वघोषित सेकुलरिस्टों के आशीर्वाद से चर्चों का देश के 30 प्रतिशत शिक्षा और 22 प्रतिशत स्वास्थ्य सेवाओं पर अधिकार है। भारत सरकार के बाद चर्च के पास सर्वाधिक भूमि है और वह भी अधिकतर देश के पॉश क्षेत्रों में। भारत में कैथोलिक चर्च के छह कार्डिनलों में एक भी दलित नहीं है। 30 आर्चबिशप में कोई दलित नहीं है। 175 बिशप में केवल 9, तो 25 हजार कैथोलिक पादरियों में 1,130 दलित—ईसाई हैं। क्या चर्च व्यवस्था में दलित—ईसाइयों की भागीदारी सुनिश्चित किए बिना, मतांतरित ईसाइयों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव संभव है?

चर्चों में दलित—ईसाइयों की स्थिति से स्पष्ट है कि उन्हें सामाजिक प्रतिष्ठा और आर्थिक संपन्नता का स्वप्न दिखाकर केवल छला ही गया है। कुछ वर्ष पहले दलित ईसाइयों के एक प्रतिनिधिमंडल ने संयुक्त राष्ट्र के तत्कालीन महासचिव बान की मून के नाम एक ज्ञापन देकर आरोप लगाया था कि कैथोलिक चर्च और वेटिकन, उनका उत्पीड़न कर रहे हैं और चर्च अधिष्ठानों में उनके साथ जातिवाद के नाम पर भेदभाव किया जा रहा है। इस संकट का समाधान तभी होगा, जब समय रहते चर्च—ईसाई मिशनरियों के मतांतरण अभियान पर पूर्ण अंकुश लगा दिया जाए। (2 जून)

लेखक पूर्व सांसद तथा दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं।

editorialbp@nayaindia.com

हिंदू पुरुषों की हत्या कर महिलाओं को उठा ले गए थे रोहिंग्या आतंकी



लाखों रोहिंग्या मुसलमानों को म्यांमार से भागकर बांग्लादेश, भारत समेत कई पड़ोसी देशों में शरण लेने को मजबूर होना पड़ा है। हालांकि इनके साथ एक काला अध्याय भी जुड़ा है। दरअसल, इसी समुदाय के कुछ आतंकियों ने कुछ समय पहले हिंदुओं का नरसंहार किया था। ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हत्या करने, गांवों में आग लगाने, प्रताड़ित करने के साथ ही बड़ी संख्या में महिलाओं का रेप भी किया था।

ऐमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक जान बचाकर भागने वाली कई हिंदू महिलाओं ने बताया कि 25 अगस्त 2017 को सुबह के करीब 8 बजे रोहिंग्या आतंकियों के समूह (अराकान रोहिंग्या सॉल्वेशन आर्मी, ARSA) ने अह नॉक खा गांव में हिंदुओं के घरों पर हमला बोल दिया। कुछ आतंकी काले ड्रेस में थे और कुछ सामान्य कपड़ा पहने थे। आतंकियों ने उस समय गांव में मौजूद 69 हिंदू पुरुषों, महिलाओं और बच्चों को उठा लिया। कुछ घंटे बाद उन्होंने ज्यादातर पुरुषों की हत्या कर दी और महिलाओं को अपने साथ लेकर चले गए।

काले कपड़ों में थे आतंकी

22 साल की बीना बाला बताती हैं कि वह उन 8 महिलाओं में से एक थीं, जिन्हें आतंकी अगवा कर बांग्लादेश ले गए। उन्होंने बताया, सुबह का समय था और मैं उस समय पूजा कर रही थी। वे हमारे घर में घुस आए। उनमें से कुछ काले कपड़ों में थे। मैंने उन्हें पहचान लिया था... वे हमारे गांव के ही थे।

बीना बताती हैं कि उन लोगों ने हमारे मोबाइल फोन जब्त कर लिए और हमें बाहर एक जगह खड़ा कर दिया, जहां और भी हिंदुओं को खड़ा किया गया था। उन्होंने ऐमनेस्टी इंटरनेशनल को बताया, 'उनके पास धारदार हथियार और लोहे की छड़ें थीं। उन्होंने हमारे हाथों को पीछे की तरफ बांध दिया और

आंखों पर पट्टी बांध दी। मैंने उनसे पूछा कि वे क्या कर रहे हैं। उनमें से एक ने कहा कि तुम दूसरे धर्म के हो, तुम यहां नहीं रह सकते हो। उन्होंने हमें पीटा और आखिरकार हमे अपने गहने और पैसे उन्हें देने पड़े।

भागने का मौका नहीं मिला

उसी दिन हिंदुओं के दूसरे गांव ये बॉक क्यार में 46 पुरुष, महिलाएं और बच्चे गायब हो गए। उनका कुछ पता नहीं चला। हमले के समय 24 साल की रीका धर भी घर पर ही थीं। उन्होंने ऐमनेस्टी को बताया, हमें भागने का कोई मौका नहीं मिला। रोहिंग्या मुसलमानों ने हमारे गहने ले लिए...हमारी आंखों पर पट्टी बांध दी गई और हाथ भी बांध दिए गए। दूसरे गांववालों की तरह रीका भी हमलावरों को पहचान रही थीं।

पुरुषों को मारा, महिलाओं को जंगल में ले गए

हिंदुओं को आतंकी गांव से बाहर ले गए और सबसे पहले उनके आईडी कार्ड्स को जला दिया गया, जो उन्होंने पहले ही छीन लिए थे। आतंकियों ने हिंदू पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग कर दिया। इसके बाद महिलाओं को लेकर जंगल में चले गए। इस दौरान 53 हिंदुओं की हत्या की गई थी। इनमें 20 पुरुष, 10 महिलाएं और 23 बच्चे थे, जिनमें से 14 बच्चों की उम्र 8 साल से भी कम थी।

इस्लाम कबूलने की बात पर जिंदा बचे

केवल 16 लोगों (8 महिलाएं और उनके 8 बच्चों) की जान बच सकी क्योंकि ये इस्लाम स्वीकार करने को राजी हो गए थे और उसके बाद इन्हें रोहिंग्या आतंकियों के साथ शादी करना था। 20 साल की फर्मीला ने ऐमनेस्टी को बताया, मुस्लिम लोग हाथों में तलवार लेकर आए। तलवारों पर खून लगा हुआ था। उन्होंने हमसे कहा कि हमारे पतियों को उन लोगों ने मार डाला।

18 साल की राज कुमारी ने बताया, उन्होंने पुरुषों को मार डाला। हमसे कहा गया था कि उनकी तरफ न देखें... हम झाड़ियों में छिप गए थे। मेरे चाचा, मेरे पिता, मेरे भाई सभी को उन लोगों ने मार डाला। पुरुषों को मारने के बाद उन्होंने कई महिलाओं को भी मार डाला।

फर्मीला बताती हैं, मैंने देखा कि कुछ लोग महिला के सिर और बाल को पकड़े हुए थे तभी दूसरे लोगों ने छुरे से उसका गला काट दिया। आशंका जताई जा रही है कि रोहिंग्या मुसलमानों के साथ आतंकी भी दूसरे देशों में शरण ले सकते हैं। रोहिंग्या आतंकियों ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में हिंदुओं का कत्लेआम कैसे किया था, ऐमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में इस बारे में विस्तार से जानकारी दी है। आतंकियों ने कम से कम 99 हिंदुओं का कत्ल किया था।

झूठे बयान भी दिलवाए गए

28 अगस्त को बांग्लादेश पहुंचने पर 8 हिंदू महिलाओं से जबरन फर्जी विडियो बयान दिलवाए गए। अपहरणकर्ताओं ने उनसे कहा कि अगर कोई पूछता है तो कहना है कि रखाइन के स्थानीय लोगों और सेना ने हम पर हमला किया था। बीना बाला बताती हैं, उन्होंने कहा था कि कोई पूछता है तो यही कहना है वरना मार दी जाओगी। कुछ समय बाद ही ये विडियो फेसबुक पर पोस्ट किए गए। इसके बाद उत्तरी रखाइन प्रांत के हिंदू समुदाय के लोगों ने बांग्लादेश में अपने दोस्तों से महिलाओं को ढूंढने को कहा। हिंदू शरणार्थियों को अलग रखा गया और बांग्लादेश के सुरक्षाबलों ने उनकी सुरक्षा की। बाद में अक्टूबर में 16 महिलाओं को म्यांमार वापस भेज दिया गया।

(navbharattimes.indiatimes.com, 2 Jun)

मेजर गोगोई पर कोई मुकदमा नहीं

पुलिस ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट, लड़की बालिग



श्रीनगर, 1 जून। होटल में बुकिंग अस्वीकार किए जाने के दौरान होटल स्टाफ के साथ कहासुनी मामले में सेना के मेजर लीतुल गोगोई के खिलाफ कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है। इसकी जानकारी पुलिस ने श्रीनगर की एक अदालत में पेश की गई अपनी स्टेटस रिपोर्ट में दी है।

श्रीनगर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने पुलिस से स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने को कहा था। मानवाधिकार कार्यकर्ता एहसान उनतू की याचिका पर उन्होंने यह निर्देश दिए थे।

याचिका में उनतू ने पुलिस से यह पूछने को कहा था कि पुलिस ने इस मामले में क्या कार्रवाई की है और सेना के अधिकारी को क्यों जाने दिया। पुलिस ने अदालत में पेश रिपोर्ट में कहा है कि जो लड़की उस समय सेना के अधिकारी के साथ थी, उसकी ओर से कोई भी शिकायत दर्ज नहीं की गई है।

मामला संज्ञेय नहीं पाया गया था। लड़की को उसके परिवार और सेना अधिकारी लीतुल गोगोई व उनके सहयोगी समीर अहमद मल्ला को उनकी सेना यूनिट को सौंप दिया गया था।

रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि मजिस्ट्रेट के सामने

समीर मल्ला की गाड़ी में होटल पहुंची थी। इस मामले में पुलिस की ओर से अदालत में पेश रिपोर्ट में दर्ज तथ्यों ने सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है।

यह था मामला

23 मई को उस समय विवाद खड़ा हुआ था जब यह खबर फैली थी कि सेना के एक अधिकारी को एक नाबालिग लड़की के साथ स्थानीय होटल से पुलिस ने गिरफ्तार किया जो यौन शोषण की मंशा से उसे साथ लेकर आया था। हालांकि यह मामला ज्यादा तूल उस समय पकड़ने लगा जब खबर यह सामने आई कि पकड़ा गया अधिकारी वह है, जिसने बडगाम जिले में लोकसभा चुनाव के दौरान एक स्थानीय युवक को ह्यूमन शील्ड बनाया था।

लड़की ने बयान दिया था कि वह गोगोई की दोस्त है। उसके साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई थी और वह अपनी मर्जी से उनके साथ गई थी। पुलिस ने रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि लड़की गोगोई के साथ उनके साथी

पुलिस ने अदालत के सामने लड़की के स्कूली दस्तावेज भी पेश किए हैं जिसमें लड़की की जन्म तिथि 13 अक्टूबर, 1998 है। आधार कार्ड पर उसकी उम्र 18 साल से ऊपर है।

www.amarujala.com

नई दिल्ली, (एजेंसी) 28 मई। पाकिस्तान के नागरिक अधिकार समूहों ने इस आदेश की आलोचना की है। गिलगित-बाल्टिस्तान के संबंध में इस्लामाबाद के तथाकथित आदेश को लेकर भारत ने रविवार को पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त सैयद हैदर शाह को तलब किया। भारत ने उनसे कहा कि उनके देश के जबरन कब्जे वाले क्षेत्र के किसी भी हिस्से के दर्जे में बदलाव करने के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उसने शाह को सूचित किया कि 1947 में हुए विलय के आधार पर पूरा जम्मू कश्मीर राज्य भारत का अभिन्न हिस्सा है और गिलगित-बाल्टिस्तान इलाका उस राज्य में शामिल है।

इसमें कहा गया है कि भारत में पाकिस्तान के उप-उच्चायुक्त को तलब किया गया और पाकिस्तान के

गिलगित-बाल्टिस्तान को पाक में

मिलाने की चाल; भारत का जुबानी पलटवार



तथाकथित गिलगित-बाल्टिस्तान आदेश, 2018 के खिलाफ सख्त विरोध जताया गया। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शाहिद खकान अब्बासी ने गिलगित-बाल्टिस्तान पर 21 मई के एक आदेश के जरिए क्षेत्र के मामलों से निपटने के स्थानीय परिषद के ज्यादातर

अधिकार ले लिए। पाकिस्तान के नागरिक अधिकार समूहों ने इस आदेश की आलोचना की है।

विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान के जबरन और अवैध कब्जे वाले क्षेत्र के किसी भी हिस्से के दर्जे में बदलाव के लिए किसी भी कार्रवाई का कोई कानूनी आधार नहीं है और वह पूरी तरह से अस्वीकार्य भी है। पाकिस्तान को कब्जे वाले क्षेत्रों के दर्जे में बदलाव के बदले अवैध कब्जे वाले सभी क्षेत्रों को तुरंत खाली कर देना चाहिए।

मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तानी उप-उच्चायुक्त को यह भी कहा गया कि

शेष पृष्ठ 21 पर.....

कश्मीर

दोहरे मापदंड कब तक?

जम्मू-कश्मीर पुनः चर्चा में है। उसके दो मुख्य कारण हैं। पहला—सरकारी निर्देश पर रमजान के दिनों में घाटी में पत्थरबाजों और आतंकियों पर सुरक्षाबलों का एकतरफा संघर्ष विराम। और दूसरा—प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रदेश को विकास की सौगात। कश्मीर की संकटमयी स्थिति के लिए अक्सर 'असंतोष' शब्द का प्रयोग किया जाता है। बीते सात दशकों से जिस 'नाराजगी' के कारण घाटी के अधिकतर युवा (स्कूली छात्र-छात्राओं सहित) भारत की मौत की दुआ मांगकर सुरक्षाबलों पर पत्थर बरसाने और आतंकियों से सहानुभूति रखने के लिए विवश हो रहे हैं— क्या वह प्रधानमंत्री के विकास मंत्रों या फिर रमजान में एकतरफा संघर्ष विराम जैसे कदमों से दूर हो सकती है?

19 मई को श्रीनगर में किशनगंगा हाइड्रोइलेक्ट्रिक विद्युत परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू-कश्मीर के "गुमराह" युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। उन्होंने कहा, 'शांति और स्थिरता का कोई विकल्प नहीं है। राज्य के भटके हुए नौजवानों द्वारा उठाया गया हर पत्थर, हर हथियार उनके अपने राज्य को अस्थिर करता है, अब राज्य को इस अस्थिरता के माहौल से बाहर निकलना ही होगा।' आगे प्रधानमंत्री कहते हैं, 'मैं चाहता हूँ कि सभी लोग जम्मू-कश्मीर के विकास में अपनी ऊर्जा लगाएं। सभी समस्याओं और मतभेदों का बस एक ही समाधान है— विकास, विकास और विकास।' अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री ने लेह-लद्दाख को जोड़ने वाली जोजिला सुदूर परियोजना और श्रीनगर रिंग रोड का भी शिलान्यास किया था।

कश्मीर संकट को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में ही नहीं, अपितु देश के कई पूर्ववर्ती प्रधानमंत्रियों ने भी इस दिशा में भरसक प्रयास किए हैं। 2004-14 के संप्रगकाल

में प्रधानमंत्री रहे डॉ. मनमोहन सिंह ने हिंसाग्रस्त कश्मीर को शांत करने हेतु कई प्रयास किए, जिसमें सरकार द्वारा गठित वार्ताकार समूह ने पाकिस्तान परस्त अलगाववादियों से बात की। 1999-2004 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने "कश्मीरियत, जम्हूरियत और इंसानियत" का नारा दिया। 1970 के दशक में अति-सांप्रदायिक शेख अब्दुल्ला से समझौता करके तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें फिर से जम्मू-कश्मीर का



अब सभ्य समाज के लिए थिरूमणि और वे स्कूली बच्चे मासूम हैं या फिर "असंतुष्ट" मजहबी उन्मादी?

मुख्यमंत्री बनाया। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तो शेख अब्दुल्ला के कथनानुसार ही जम्मू-कश्मीर का भविष्य निर्धारित कर दिया था, जो वर्तमान कश्मीर संकट के बीज से कमतर नहीं है।

राजनीतिक पहल के साथ-साथ आर्थिक रूप से भी जम्मू-कश्मीर पर केंद्र की कृपा होती रही है। वर्तमान समय में राज्य में 60 हजार करोड़ रुपये की केंद्रीय परियोजनाओं पर काम चल रहा है, जिसका बड़ा भाग पर्यटन और आधारभूत संरचनाओं को सुदृढ़ और आधुनिक करने में व्यय हो रहा है। प्रदेश को मिलने वाला केंद्रीय ग्रांट भी देश में

सर्वाधिक है। अब यदि विकास परियोजनाएं और राजनीतिक प्रयासों से कश्मीर में आमूलचूल परिवर्तन संभव होता, तो वर्षों पहले ही इस भू-भाग में शांति स्थापित हो चुकी होती और देश के अन्य क्षेत्रों की भांति यह सामान्य जनजीवन का मूर्त रूप बन चुका होता। क्या ऐसा हुआ?

घाटी में रमजान के दिनों में एकतरफा संघर्षविराम की सरकारी घोषणा को आतंकी संगठन लश्कर खारिज कर चुका है, ऐसे में कश्मीर में सुरक्षाबलों का "ऑपरेशन ऑलआउट" का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इस सफल सैन्य अभियान के अंतर्गत, इस वर्ष सुरक्षाबल अबतक 70 आतंकियों को ढेर कर चुके हैं। साथ ही जुलाई 2016 में मारे गए हिज्बुल आतंकी बुरहान वानी के सभी 11 जिहादी साथियों को भी जन्मत पहुंचा दिया गया है। हाल में सुरक्षाबलों

ने जिन आतंकियों को ठिकाने लगाया है, उसमें कश्मीर विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र विषय पढ़ाने वाला सहायक प्रोफेसर मोहम्मद रफी भट भी शामिल था। अब यदि कश्मीर में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी घाटी में फैले कथित "असंतोष" और "भटकाव" के मुख्य कारण हैं, तो भट जैसे शिक्षित, नौकरीपेशा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र युवा-मानवता के शत्रु क्यों बन रहे हैं?

दशकों से कश्मीर में जिस 'असंतोष' को अशिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी और विकास के चश्मे से देखा गया है, आज भी ऐसा हो रहा है— वह वास्तव में

शेष पृष्ठ 20 पर....



पत्थर गढ़ी

अजेश अग्रवाल

अंबिकापुर शहर के करीब 60 कि०मी० की दूरी पर बगीचा ब्लाक है। उसके बच्छरांव गांव थाना नारायणपुर और बगीचा में पिछले दिनों गांव के कुछ लोगों के द्वारा ग्राम सभा का आयोजन कर कुछ ऐसे प्रस्ताव पास किए गए जिससे सरगुजा अंचल में ही नहीं छत्तीसगढ़ राज्य और देश के बाहर भी इसकी काफी चर्चा होने लगी है।

पत्थरगढ़ी क्या है ?

बगीचा ब्लाक के बच्छरांव गांव में कुछ लोगों के द्वारा एक ग्राम सभा का आयोजन किया जाता है जिसमें देश के संविधान के पांचवी अनुसूची को उद्धृत कर यह प्रस्ताव रखा जाता है, सावधान यह अनुसूचित क्षेत्र है, हमारे ग्राम में पांचवी अनुसूची लागू है यहां कोई भी बाहरी व्यक्ति और प्रशासन ग्राम सभा के स्वीकृति के बिना ग्राम में प्रवेश नहीं कर सकता। जल जंगल और जमीन पर आदिवासियों का अधिकार है, इसलिए इन तीन विषयों पर पॉलिसी बनाना उनका दोहन करना यह सब कार्य ग्रामसभा ही करेगी।

संविधान में पांचवी अनुसूची का उल्लेख है जिसमें कहा गया है कि राज्य सरकारें एक कानून के द्वारा इस अनुसूची के अनुरूप आदिवासी क्षेत्रों के

लिए निम्न विषयों पर ग्राम सभा को अधिकार प्रदान कर सकती है जिसमें मुख्य रूप से जंगलों में उत्पादित उत्पादों का दोहन प्रोसेसिंग और विक्रय पर ग्राम सभा का अधिकार होगा। हाट बाजार पर विनिमय बनाना नियम बनाना और विभिन्न प्रकार के गांव के विकास के लिए नीतिगत फैसले लेना निर्माण

एक प्रश्न यह भी उठता है जो लोग सरहुल सरना पूजा करते थे, ग्राम देवता की पूजा करते थे, प्रकृति और भूमि की पूजा करना जिनके संस्कृति में रहा है, क्या क्रास पहने के बाद ऐसी परंपराओं को छोड़ने से आदिवासी कहलाने का अधिकार रखते हैं। यदि नहीं तो क्यों न ऐसे सनातन आदिवासी, रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले कनवर्टेड आदिवासियों के विरुद्ध लोगों को जागरूक कर सनातन आदिवासियों के हितों की रक्षा हेतु कार्य किया जाए।

ऐसी संस्थाएं जो आदिवासियों की भूमि, आदिवासियों के नाम खरीद कर बड़े-बड़े बिल्डिंग बना रहे हैं, उनकी जमीनों को भू-राजस्व संहिता की धारा 170 ख के अन्तर्गत विक्रेता को वापस सौंपी जाए या फिर शासन को कब्जे में लेने हेतु प्रेरित किया जाए। ज्यादा जरूरत इस बात की है कि सभी गरीब आदिवासी संगठित

कार्यों की देखरेख करना आदि सब कार्यों पर ग्राम सभा के अधिकार होंगे।

बच्छराज गांव में करीब 600 लोग क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले हैं और 1300 लोग हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं जिसमें अधिकांश आदिवासी निवासरत हैं। क्रिश्चियन धर्म को मानने वाले पूर्व प्रशासनिक/रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हरमन किण्डो, रिटायर्ड ओएनजीसी अधिकारी जोसेफ मिंज, दाउद कुजूर, सुभाष कुजूर, पीटर खेम जैसे 45 लोग अपने क्रिश्चियन समुदाय के परिवार वालों के साथ ही साथ पूरे गांव वालों के समक्ष प्रस्ताव पास कर पूरे क्षेत्र को अशांत कर दिए। उनकी मंशा स्पष्ट है कि ग्राम सभा के अधिकारों की पैरवी न कर अपने संगठन की ताकत को दिखाना और आदिवासियों के बीच यह कोशिश करना कि गैर आदिवासी हमारे शोषण करने वाले लोग हैं। इस प्रकार आदिवासियों के बीच यह भ्रम पैदा करना कि क्रिश्चियन समुदाय के जो पदाधिकारी हैं जिन्होंने बैठक आहूत की गई थी वे ही आदिवासियों के मसीहा हैं।

बच्छरांव गांव में पास प्रस्ताव कुछ ऐसा ही है क्योंकि 600 क्रिश्चियन के परिवार संगठित हैं, उन्हें एक ही मकसद

होकर क्रीमीलेयर/उच्च वर्ग के आदिवासियों को रिजर्वेशन के लाभ से वंचित करने हेतु मुहिम चलाएं।

इसे मजबूती तभी मिलेगी जब रिजर्वेशन का लाभ लेने वाले और लाभ अप्राप्त के बीच का अंतर समझाया जायेगा क्योंकि कनवर्टेड आदिवासियों ने ही रिजर्वेशन का अधिकतम लाभ प्राप्त किया है। हमारे राजनैतिक लोगों ने भी वोट बैंक के खातिर कन्वर्जन को बढ़ाने में साथ दिया है। पत्थरगढ़ी में उद्धृत जानकारी असंवैधानिक और लोगों को गुमराह करने वाली है।

यह नहीं भूलना चाहिए कि उत्तर छत्तीसगढ़ में माओवादी शांत हुए हैं खत्म नहीं, पत्थरगढ़ी माओवाद और कनवर्टेड आदिवासी का संयुक्त परिणाम है जो देश और समाज दोनों ही के लिए चिंता की बात है।

ग्राम सभा के अधिकार निश्चित ही असीमित हैं। पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा द्वारा पारित प्रस्ताव को राज्य

पर काम करना है कि किसी तरह से समाज में अशांति फैले, लोग बिखरते जाएं क्योंकि गांव में यदि हम हिंदू धर्मावलंबियों के रिहाइशी का आकलन करें तो पाते हैं कि यह गांव के अंदर 5 से 10 तक अलग-अलग जाति और समूह में लोग निवासरत हैं जिसे टोला या मोहल्ला कहते हैं। उनका आपस में बातचीत होती है परन्तु एक दूसरे के यहां पीना खाना और इससे आगे एक दूसरे के परिवारों में शादी करना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। दूसरी ओर क्रिश्चियन कम्युनिटी चाहे किसी भी जाति से कन्वर्ट होकर आए हों, जब क्रिश्चियन बन जाते हैं तो उनके यहां

आपस में खाना पीना तो सामान्य सी बात है, शादी ब्याह भी होने लगते हैं। इसी कमजोरी का फायदा दूसरे धर्मावलंबी उठाते हैं।

आम आदमी में भी यदि आदिवासियों की बात करें तो आदिवासियों का क्रीमीलेयर/उच्च वर्ग हमेशा से आदिवासियों का ही शोषण करने में सबसे आगे हैं, क्योंकि उनकी जमीन कोई सामान्य वर्ग का व्यक्ति खरीद नहीं सकता। दूसरे आदिवासी बंधुओं के पास धन की कमी होने के कारण वह अपने भाइयों की जमीनों को खरीद नहीं सकते, कुछ गिने चुने उच्च वर्ग आदिवासियों के अधिकारियों के

पास में धन होने के कारण या राजनीति में होने के कारण वही लोग आदिवासियों की जमीन एकदम सस्ते कीमतों पर खरीद लेते हैं।

आदिवासियों का शोषण करने वाले उच्चवर्गीय आदिवासी ही हैं लेकिन यह बात आदिवासियों को समझ में नहीं आती?

वर्तमान समय में शासन जंगलों में निवासरत लोगों को पट्टा देते आ रही है, परिणामस्वरूप लोगों में जंगल काट कर कब्जा करने की प्रवृत्ति बनती जा रही है। जंगल कम हो गए हैं, जंगली जानवर रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं। अकेले छत्तीसगढ़ में अभी तक 200 से अधिक लोगों की जान हाथियों के द्वारा ली जा चुकी है।

ऐसे पट्टाधारी अपने पट्टे की जमीन बेच कर फिर नए कब्जे के लिए जंगल की ओर बढ़ जाते हैं।

हमारे व्यवसायों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो धन का अत्यधिक संग्रह या आसान कमाई की इच्छा से समाज के गलत कार्यों को भी बढ़ावा देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति की जरूरत पर धन को उधार में देना और उस पर 2-4 परसेंट ब्याज कौन कहे 10 प्रतिशत ब्याज महीने भर का वसूल करना। हमें दिखाई देता है, उदाहरण सुनाई देते हैं। साथ ही ऐसे व्यवसाय, ऐसे बच्चों को जो किसी गलत रास्ते पर चल रहे हैं, घर वालों की जानकारी के अभाव में जुआ/सट्टा/रेसिंग या और न जाने किस प्रकार के गलत आचरण में पड़े हुए हैं और उन्हें समाज के ही कुछ लोग धन मुहैया कराते हैं। उनसे ब्लैंक चेक साइन करा लेते हैं, लिखित में ले लेते हैं।

यदि हमारे पुराने सामाजिक ताना बाना की बात करें तो वह समय था जब गांव का कोई व्यक्ति गांव के किसी दूसरे परिवार के किसी बच्चे को गलत जगह, गलत हरकत, गलत कार्य करते हुए देखता था तो वह एक अपना सामाजिक दायित्व का निर्वहन करते हुए उस बच्चे को डांटकर जरूरत पड़ी तो थप्पड़ मार कर भी उसे वहां से भगा देता था। यदि ऐसी स्थिति दुबारा-तिबारा देखने को मिलती थी तो उनके घर वालों तक भी यह संदेश देकर आता था, जिसमें ऐसे युवा पीढ़ी किसी गलत आचरण के

शेष पृष्ठ 21 पर....



विचारणीय प्रश्न

शासन भी नकार नहीं सकती इसके लिए उच्च न्यायालय से नीचे कोई न्यायालय सुनवाई भी नहीं कर सकती।

ग्रामसभा और संविधान की पांचवी अनुसूची दो अलग-अलग परंतु संबंधित विषय हैं। यह जागरण का विषय है कि प्रत्येक ग्रामवासी ग्रामसभा के महत्व को समझे, इससे बड़ी बात की ग्रामसभा की कार्यवाही पारदर्शी और सभी के सहभागिता पर आधारित हो। परन्तु सच्चाई कुछ और ही देखने को मिलती है। सरपंच सचिव एजेण्डा को सभी के सामने रखते ही नहीं हैं, हस्ताक्षर होने के बाद रजिस्टर में लिखने का कार्य करते हैं।

उसी प्रकार सामाजिक अंकेक्षण का कार्य भी ग्राम सभा में खानापूति के रूप में होता है। जब तक जनता जागरूक नहीं होगी, स्वार्थी तत्व अपने

व्यक्तिगत लाभ के लिए आदिवासियों का शोषण करते ही रहेंगे।

जरूरत लोगों को जागरूक करने उनके अधिकारों को बताने, योजना बनाने और निगरानी करने की है, पत्थरगढ़ी जैसी घटनाएं कभी नहीं होंगी। अशिक्षित लोग ही दूसरों के बहकावे में आते हैं, इसलिए सरकार को भी चाहिए कि ग्रामसभा के महत्व को प्रत्येक लोगों तक पहुंचाए।

पाठकों की जानकारी के लिए लिखना उचित होगा छत्तीसगढ़ शासन ने संविधान के अनुसार पांचवी अनुसूची के आवश्यक दिशा निर्देश लागू किए जाने हेतु आवश्यक कानून पास कर लागू किया हुआ है, इसी के परिणामस्वरूप पांचवी अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायतों और ग्राम सभा की अध्यक्षता आदिवासियों के द्वारा ही की जाती है।



हिन्दू संस्कृति में रचा-बसा मुस्लिम बहुल इण्डोनेशिया



पुष्पेश पंत

आबादी के लिहाज से इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश है पर यहां हिन्दू संस्कृति का असर काफी प्रभावशाली है। इंडोनेशिया अपनी साझी संस्कृति के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के दौरे पर हैं और वो जकार्ता में महाभारत के अहम किरदार अर्जुन की मूर्ति भी देखने जाएंगे। इंडोनेशिया के बाली द्वीप में हिंदू बहुसंख्यक हैं।

भारत और इंडोनेशिया के रिश्ते हजारों साल पुराने हैं। ईसा के जन्म से पहले से ही भारत के सौदागर और नाविक वहां जाते रहे हैं। यही कारण है कि इंडोनेशिया और भारत में काफी सारी सांस्कृतिक समानताएं देखने को मिलती हैं। प्राचीन काल से ही भारतीय सौदागर और नाविकों के आने-जाने के कारण इंडोनेशिया में न सिर्फ हिंदू धर्म बल्कि बौद्ध धर्म का भी प्रभाव नजर आता है।

इंडोनेशियाई भाषा, स्थापत्य, राजशाही और मिथकों पर भी इन धर्मों का असर है। उदाहरण के लिए

इंडोनेशिया के पुराने साम्राज्यों के नाम श्रीविजया और गजाह मधा आदि हैं। यही नहीं, भाषा के मामले में भी कई समानताएं हैं। उनकी भाषा को बहासा इंदोनेसिया कहते हैं। उनकी भाषा पर संस्कृत का गहरा प्रभाव है। उदाहरण के लिए मेघावती सुकार्णोपुत्री, जो कि इंडोनेशिया की पांचवीं राष्ट्रपति रही हैं।

गहरा सांस्कृतिक साम्य

इंडोनेशिया में अगर आप और रामायण का जिक्र करेंगे तो वे कहेंगे कि ये तो हमारे ग्रंथ हैं। वहां के उत्सवों और झांकियों आदि में इन ग्रंथों के पात्र कठपुतलियों के रूप में नजर आ जाते हैं। जैसे कि वहां चमड़े की कठपुतलियों के शो में ऐसे ही कुछ विचित्र पौराणिक पात्र देखने को मिलते हैं। कहीं, कौरवों में से विचित्र हीरो निकल आता है तो कहीं हनुमान नजर आ जाते हैं।

उनके रामायण या महाभारत के कुछ प्रसंग भिन्न होते हैं, मगर कथानक वही रहता है। इंडोनेशिया के प्राचीन श्रीविजया और गजाह मधा जैसे साम्राज्यों में भारतीय संस्कृति की गहरी

छाप है। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह छाप अकेले हिंदू धर्म की नहीं है बल्कि बौद्ध धर्म की भी है।

इस्लाम भी भारत के रास्ते पहुंचा

इंडोनेशिया सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है। मगर यहां पर इस्लाम भी भारत के पूर्वी तट से होता हुआ पहुंचा है। यही कारण है कि इंडोनेशिया और दक्षिण एशिया, खासकर भारत के इस्लाम में कुछ समय पहले तक समानता रही है। दोनों ही जगहों का इस्लाम सूफीवाद से प्रभावित उदार और मानवीय परंपराओं को मानने वाला रहा है। मगर पिछले कुछ समय से इंडोनेशिया में कट्टरपंथ बढ़ा है।

वृहत्तर भारत

प्रसिद्ध फ्रांसीसी विद्वान और इतिहासकार पॉल सीडीस ने कई वर्ष पहले किताब लिखी थी— द हिंदुआइज्ड स्टेट्स ऑफ साउथईस्ट एशिया (अनुवादित नाम)। इस किताब में उन्होंने श्रीविजया और यवद्वीप यानी जावा आदि का जिक्र किया था जो आज इंडोनेशिया के भाग हैं। जब हम आधी सदी पहले स्कूल में पढ़ते थे, तब राजनीतिक समझदारी या पॉलिटिकल करेक्टनेस इतनी नहीं हुआ करती थी। इस सारे इलाके को वृहत्तर भारत या ग्रेटर इंडिया कहा जाता था।

बाद में स्वाधीनता संग्राम के बाद जब ये देश आजाद हुए तो इनके स्वाभिमान को देखते हुए भारत ने इन्हें अपने सांस्कृतिक प्रभावक्षेत्र में कहना बंद कर दिया और यह जगह दक्षिणपूर्व एशिया के नाम से पहचानी जाने लगी।

इंडोनेशिया में इसलिए है

हिंदू-बौद्ध संस्कृति का प्रभाव

सातवीं सदी में व्यापार के कारण इंडोनेशिया में शक्तिशाली श्रीविजया साम्राज्य पनपा। इस साम्राज्य पर हिंदू और बौद्ध धर्म का भी प्रभाव था, जो व्यापारियों के कारण आया था आठवीं और 10वीं सदी में जावा में षक बौद्ध सैलेंद्र और हिंदू मतारम वंश फले फूले। इसी काल में जावा में हिंदू-बौद्ध कला और स्थापत्य की पुनर्स्थापना हुई थी। इस काल में बने कई स्मारक आज भी इंडोनेशिया में देखने को मिलते हैं। 13वीं सदी के आखिर में पूर्वी जावा में हिंदू

क्या मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की फोटो छपी है? हां, यह सच है

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाल ही में इंडोनेशिया दौरे गए थे। उस दौरान सोशल मीडिया पर एक ऐसी खबर वायरल हुई जिसको देखकर सब अचंभे में पड़ गए कि क्या सच में ऐसा है? इन खबरों में दावा किया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े मुस्लिम देश इंडोनेशिया के नोट पर गणेश जी की तस्वीर छपी है।

तो आइए जानते हैं सच क्या है

वायरल खबर में जिस नोट की बात हो रही है, वह इंडोनेशियाई रुपियाह का 20,000 का नोट है। यह जानकर आपको हैरानी होगी कि इस नोट पर सच में गणेश जी की तस्वीर छपी है। इस नोट को इंडोनेशियाई सरकार ने 1998 में जारी किया था, लेकिन 10 साल के प्रचलन के बाद 2008 के अंत में इसे बंद कर दिया गया।

अब सवाल यह उठता है कि इंडोनेशिया जैसे मुस्लिम बाहुल्य देश में,

जहां हिंदुओं की आबादी 2 फीसदी से भी कम है।

सरकार ने नोट पर गणेश जी की फोटो आखिर क्यों छपी?

दरअसल, इंडोनेशिया में हिंदू और मुस्लिम के बीच कोई फर्क नहीं किया जाता। वहां हिंदू देवी-देवताओं को बहुत सम्मान मिलता है। 20,000 के इस वायरल नोट पर गणेश जी के साथ इंडोनेशिया के पहले शिक्षा मंत्री श्री हजर देवांत्रा की तस्वीर भी है। देवांत्रा इंडोनेशिया के स्वतंत्रता सेनानी थे और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम किया था। इस नोट के पीछे क्लास रूम की तस्वीर बनी है, जो नोट की थीम शिक्षा को दर्शाती है। हो सकता है इसी वजह से उस नोट पर गणेश जी की भी फोटो छपी गई हो क्योंकि वहां भगवान गणेश को बुद्धि का देवता माना जाता है।

वैसे, इंडोनेशिया के नोट पर गणेश

जी की फोटो छपने से संबंधित एक और किवदन्ती है। कहते हैं कि जब 1997 में कई एशियाई देशों की मुद्रा का अवमूल्यन हो रहा था, तो इंडोनेशिया में भी भयंकर आर्थिक संकट हो गया था। फिर 1998 में 20,000 का एक नया नोट जारी किया गया, जिस पर भगवान गणेश की तस्वीर छपी गई। इसके अगले ही साल 1999 में इंडोनेशिया की मुद्रा की स्थिति में तेजी से सुधार हुआ। यह संयोग भी हो सकता है लेकिन लोगों का मानना है कि गणेश जी की वजह से ही वहां की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है।

आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विष्णु के वाहन माने जाने वाले गरुड़ के नाम पर इंडोनेशिया की राष्ट्रीय विमान सेवा है और इस देश का नेशनल एंब्लेम गरुड़ पंक्षील कहलाता है। हनुमान जी इंडोनेशिया के मिलिट्री इंटेलिजेंस के मैस्कॉट हैं। यहां गणेश, कृष्ण और हनुमान के साथ-साथ महाभारत-रामायण के दृश्यों को दर्शाते हुए कई डाक टिकट जारी हो चुके हैं। इंडोनेशिया के एक कॉलेज के लोगो पर भी भगवान गणेश हैं और राजधानी जकार्ता में कृष्णा-अर्जुन की मूर्तियां भी लगी हुई हैं।

(<http://m.hindi.webdunia.com>)

मजापहित साम्राज्य की स्थापना हुई थी। गजाह मधा के अधीन इसके प्रभाव का विस्तार उस क्षेत्र में हुआ जो आज इंडोनेशिया है।

समानता भी, भिन्नता भी

सदियों पहले हिंदू धर्म ही यहां नहीं पहुंचा था बल्कि बौद्ध धर्म भी इसके साथ-साथ या शायद इससे पहले इंडोनेशिया पहुंचा था। यही कारण है कि जावा द्वीप पर आपको प्रांबानन में हिंदू मंदिर भी मिलता है और बोरोबोदूर में संसार का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप भी मिलता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ पड़ने वाला इंडोनेशिया का बाली द्वीप तो हिंदू बहुल है। बावजूद इसके यहां का हिंदू धर्म भारत के हिंदू धर्म से काफी अलग है।

बाली के हिंदू धर्म का आज के हिंदुत्ववादी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। यह नहीं कहा जा सकता कि वहां पर भारत का सनातन धर्म या भक्ति परंपरा है। जैसे कि प्रसिद्ध इतिहासकार लोकेश चंद्र ने बताया है, एशिया में रामायण के

असंख्य संस्करण मिलते हैं। इसी तरह से वे भी भिन्न हैं।

हिंदू धर्म की छाप इंडोनेशिया ही नहीं, कंबोडिया और थाइलैंड में भी मिलती है। लाओस में भी लोग नमस्कार करते हैं। मगर यह नहीं कहा जा सकता कि वहां के हिंदू भारत के हिंदुओं जैसे हैं। इंडोनेशिया के हिंदुओं की मान्यताएं और रीति-रिवाज भारतीय हिंदुओं से अलग हैं। इंडोनेशिया और भारत में सांस्कृतिक समानता बहुत है, वे आपस में जुड़े भी हुए हैं, मगर दोनों के बीच

हितों का टकराव भी रहा है।

इंडोनेशिया भी एक समय वैसा बहुलवादी और समन्वयात्मक था, जैसा कभी भारत खुद को कहता था। इंडोनेशिया का नारा भी विविधता में एकता वाला है। मगर हाल ही के वर्षों में इन पुराने सांस्कृतिक रिश्तों को झटका लगा है।

लेखक सुप्रसिद्ध राजनैतिक विश्लेषक हैं।

(बीबीसी संवाददाता आदर्श राठौर के साथ बातचीत पर आधारित, 30 मई)

सुभाषित

नाभिषको न संस्कारः सिंहस्य क्रियते मृगैः ।

विक्रमार्जित-राजस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता । ।

वन के प्राणी कोई सिंह का राज्याभिषेक नहीं करते। अपने बल से अर्जित राज्य के पशुओं पर शासन करने का अधिकार उसे स्वयं ही प्राप्त हो जाता है।

(गरुड़ पुराण)



शौर्य प्रशिक्षण वर्ग

ब्रज प्रांत

आगरा, 29 मई। विश्व हिंदू परिषद 'दुर्गा वाहिनी' के शौर्य प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं और युवतियों को अपनी रक्षा स्वयं करने के गुण सिखाये जा रहे हैं। इस प्रशिक्षण शिविर में महिलाओं और युवतियों को कराटे के साथ-साथ दंड चलाने और शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस दौरान शस्त्र चलाने की ट्रेनिंग ले रही महिलाओं और युवतियों के चेहरे पर अलग ही भाव नजर आ रहा था।

एत्मादौला थाना क्षेत्र के फाउंड्री नगर स्थित जगदम्बा डिग्री कॉलेज में विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी के सात दिवसीय शिविर में महिलाओं को भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत किया जा रहा है तो वहीं असामाजिक तत्वों से कैसे निपटा जाये, यह भी सिखाया जा रहा है।

शिविर के समापन पर दुर्गावाहिनी उ० क्षे० संयोजिका रजनी टुकराल ने कहा कि गीता और निर्भया जैसी बेटियों



के साथ जो घटित हुआ वह और किसी हिंदू समाज की बेटों के साथ न हो इसलिए भारतवर्ष में बेटियों को आत्मरक्षा के गुण एनसीसी के आधार पर प्रशिक्षित किया जा रहा है जिसमें बौद्धिक और शारीरिक रूप से वे अबला के स्थान पर सबला बनें। दुर्गावाहिनी हिंदू बहिन- बेटियों की रक्षा के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

विहिप संयुक्त महामंत्री वाई० राघवुलू ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण देश के करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है जो जल्द ही पूरा होगा। संघ के विभाग संघचालक

हरिशंकर शर्मा ने कहा कि प्रत्येक हिंदू ऐसे वर्गों में अपनी बेटियों को भेजकर समाज का सुरक्षा कवच तैयार करे। समापन कार्यक्रम की अध्यक्षता पू० स्वामी दिव्यानंद जी ने की। वर्ग का संचालन शशि बहिन ने किया। वर्गाधिकारी ने सभी अतिथियों का धन्यवाद किया।

bhartendubabander@gmail.com

मध्यभारत प्रांत

मध्यभारत प्रांत का दुर्गावाहिनी शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 15 से 21 मई तक सुंदरवन नर्सरी, भोपाल में आयोजित किया गया। विहिप क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी ने सम्बोधित किया।

raktsewasamitimp@gmail.com



जयपुर

जयपुर, 21 मई। दुर्गावाहिनी- मातृशक्ति का शौर्य प्रशिक्षण वर्ग 17 मई से 24 मई तक मीरा निकेतन कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, सरदारशहर, चूरु में प्रारम्भ हुआ। शौर्य प्रशिक्षण वर्ग में सम्पूर्ण जयपुर प्रान्त से 200 युवतियां शौर्य प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं।

उद्घाटन से अब तक केन्द्रीय मंत्री मीनाक्षी ताई, केन्द्रीय सहमंत्री रास बिहारी, क्षेत्रीय मंत्री नरपत सिंह शेखावत तथा प्रान्त मंत्री किशोरी लाल ने प्रशिक्षुओं को सम्बोधित किया। vhpravindra21@gmail.com





महाकोशल

दमोह, 14 से 21 मई। केशवनगर स्थित सरस्वती शिशु मंदिर में चल रहे बजरंग दल के प्रांत शौर्य प्रशिक्षण वर्ग के समापन अवसर पर दीक्षांत कार्यक्रम में विहिप क्षेत्र मंत्री राजेश तिवारी ने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण की शुभकामनाएं प्रेषित कर हिंदू धर्म व भारत माता की सेवा में संपूर्ण जीवन व्यतीत करने का संकल्प दिलाया। ललित पारधी क्षेत्र संयोजक बजरंग दल, राजेश तिवारी प्रांत मंत्री, संजय होल्कर प्रांत संगठन मंत्री, राव उदयप्रताप सिंह प्रांत संयोजक, रविराज बिलैया वर्ग प्रमुख उपस्थित रहे।

वर्ग प्रमुख द्वारा 7 दिवसीय वर्ग में हुई गतिविधियों के विवरण की जानकारी देते हुए कहा महाकोशल प्रांत के 21 जिले से कार्यकर्ता हमारे बीच उपस्थित हैं जिसमें 113 कार्यकर्ता का प्रशिक्षण पूर्ण हुआ, हमारे 17 शिक्षकों का समूह जिसमें शारीरिक, बौद्धिक विभाग सम्मिलित है, 35 व्यवस्थापक कार्यकर्ता सहित 155 संख्या रही। कुल 21 जिलों के 74 स्थानों से आए 103 कार्यकर्ताओं में 6 प्रखण्ड स्तर के दायित्ववान, 44

बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण

खंड स्तर के दायित्ववान, 41 ग्राम स्तर के दायित्ववान रहे। दीक्षांत का संचालन बौद्धिक विभाग द्वारा किया गया।

छत्तीसगढ़

राजनांदगांव। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों से आए करीब दो सौ युवकों को बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण दे रहा है। डा. प्यारेलाल स्कूल परिसर में सात दिवसीय शिविर में उन्हें धर्म की रक्षा के गुर सिखाए जा रहे हैं। शस्त्र चालन के साथ ही शारीरिक शिक्षा भी दी जा रही है। बजरंग दल हर साल राज्य में शौर्य प्रशिक्षण देता है। इस बार छत्तीसगढ़ प्रांत का प्रदेश स्तरीय शिविर जिला मुख्यालय में लगाया गया है जो 22 मई तक आयोजित किया गया। राजनांदगांव जिले से 30 युवक शिविर में बौद्धिक और शारीरिक प्रशिक्षण ले रहे हैं।

raktsewasamitimp@gmail.com

कोंकण प्रांत

मुम्बई। 19 मई से 27 मई 2018 चारकोप कांदिवली इंडियन एजुकेशन सोसाइटी में बजरंग दल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग संपन्न हुआ। इस वर्ग में 154 उपस्थित रहे।

वर्ग का उद्घाटन मनोज वर्मा अखिल भारतीय बजरंग दल संयोजक के उद्बोधन से हुआ। वर्ग का समापन 26 मई, शोभायात्रा व प्रशिक्षण दिए हुए शिक्षार्थियों के प्रत्यक्ष के साथ एवम एडवोकेट दीपकराव गायकवाड़ के उद्बोधन के साथ समारोप हुआ।

vandemataramsolanki@gmail.com

नई दिल्ली, 30 मई, 2018। बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के ग्रीष्म कालीन प्रशिक्षण शिविरों के संबंध में एक वर्ग द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है। विश्व हिन्दू परिषद् के केन्द्रीय संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा है कि हमारी युवा इकाई बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी के प्रशिक्षण वर्ग पूर्ण रूप से



आत्मरक्षा के प्रशिक्षण को हथियारों का प्रशिक्षण कह सनसनी फैलाना बंद करें: विहिप

संगठन की गतिविधि हैं तथा गत 28 वर्षों से ये वर्ग प्रांत के अनुसार निरन्तर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें भारत की सभ्यता, संस्कृति, गौरवशाली इतिहास और दर्शन के बारे में जानकारी दी जाती है। भारत के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में उनकी भूमिका रहे, ऐसी मानसिकता निर्माण की जाती है। बौद्धिक व मानसिक विकास के साथ शारीरिक विकास की दृष्टि से आसन, प्राणायाम, ड्रिल व लक्ष्य भेद आदि का प्रशिक्षण दिया जाता है जिसे शस्त्रों के प्रशिक्षण का नाम देकर सनसनी बनाने की कोशिश की जा रही है। ये व्यायाम शहरों और गांवों की कई व्यायाम-शालाओं में देखे जा सकते हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आज पूरे देश में स्वस्थ भारत के नाम पर विभिन्न अभियान चलाये जा रहे हैं। कई सरकारी व गैर-सरकारी संगठन यह प्रयास करते हैं कि युवक-युवतियां आत्म रक्षा में सक्षम बनें। आत्म-रक्षा या समाज-रक्षा में सक्षम होना किसी को भयभीत करने के लिए नहीं होता। समाज को मजबूत करने का यह प्रयास पूर्ण रूप से वैधानिक, सकारात्मक व विकाससात्मक है।



vinodbansal01@gmail.com



परिषद शिक्षा वर्ग

इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र का परिषद शिक्षा वर्ग 20 मई से प्रारम्भ होकर 30 मई 2018 तक पंजाब प्रान्त गुरुद्वारा श्री भैणी साहिब लुधियाना में आयोजित किया गया। क्षेत्र के पांच प्रांतों के कार्यकर्ताओं की उपस्थित रही।

10 दिवसीय परिषद शिक्षा वर्ग के उद्घाटन के पर संयुक्त महामंत्री डॉ. सुरेन्द्र जैन, इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र संगठन मंत्री करुणा प्रकाश, केन्द्रीय उपाध्यक्ष बालकृष्ण नाईक, हरियाणा प्रान्त संगठन मंत्री विवेकानन्द, हिमाचल प्रदेश कार्याध्यक्ष व वर्गाधिकारी लेखराज राणा, संत रक्षपाल नामधारी जी एवं संत हरपाल नामधारी जी भी उपस्थित रहे।

इन्द्रप्रस्थ क्षेत्र के सभी 5 प्रांतों से लगभग 142 कार्यकर्ताओं ने वर्ग में भाग लिया जिसमें 15 मातृशक्ति कार्यकर्ता भी



उपस्थित रही।

बौद्धिक सत्र में विश्व हिन्दू परिषद के अंतरराष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार, केन्द्रीय प्रन्यासी मण्डल के

मार्गदर्शक दिनेश चन्द्र, केन्द्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय, बालकृष्ण नाईक व देवजी भाई रावत, बनवीर सिंह, प्रेम शंकर, लेखराज, विवेकानन्द का अलग-अलग विषयों पर उद्बोधन हुआ। चम्पत राय

जी ने 29, 30 मई दो दिन वर्ग में रहकर प्रतिदिन अलग-अलग विषयों का प्रतिपादन किया।

dharmendra312@gmail.com

चार दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग



इटावा। विश्व हिन्दू परिषद का चार दिवसीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग शिविर सरस्वती विद्या मंदिर इण्टर कालेज हॉल में सुबोध सिंह प्रान्त धर्म प्रसार प्रमुख ने दीप प्रज्ज्वलित कर और माँ भारती के चित्र पर माल्यार्पण कर सत्र का प्रथम दिवस का उद्घाटन किया।

शिविर का संचालन अवधेश भदौरिया धर्म प्रसार संयोजक द्वारा किया गया। अध्यक्षता प्रान्तीय कार्याध्यक्ष श्रीकृष्ण वर्मा ने की।

ankitacomputers.143@gmail.com

मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के लिए जिलाधिकारी को ज्ञापन

मेरठ, 18 मई। विश्व हिंदू परिषद मेरठ महानगर (मेरठ प्रान्त) ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते आरोप लगाया कि मेरठ महानगर में मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों की संख्या बढ़ गई है। विहिप के महानगर मंत्री विहिप गोपाल शर्मा ने बताया कि जिन मस्जिदों पर एक लाउडस्पीकर लगा हुआ था।

वहां पर आजकल एक की जगह बढ़कर तीन से चार संख्या हो गई है। इसके कारण आसपास रहने वाले हिंदू परिवारों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। डीएम

के नाम संबोधित ज्ञापन एडीएम एलए को सौंपते हुए विहिप कार्यकर्ताओं ने मस्जिदों पर लगे बिना अनुमति वाले लाउडस्पीकरों को उतारने की मांग की। साथ ही जिन मस्जिदों पर लाउडस्पीकरों की संख्या बढ़ाई गई हो उन्हें हटवाने की मांग रखी।



gopalkrishnanatrey@gmail.com



सामाजिक समरसता विचार गोष्ठी

जम्मू, 25 मई। जम्मू-कश्मीर प्रान्त में "सामाजिक समरसता विचार" गोष्ठी का कार्यक्रम विहिप प्रान्त मुख्यालय शक्ति आश्रम में आयोजित किया गया। विश्व हिन्दू परिषद् के अनेक आयाम है, जिसमें सामाजिक समरसता मुख्य आयाम है। विश्व हिन्दू परिषद् के केन्द्रीय सहमंत्री एवं अखिल भारतीय सामाजिक समरसता प्रमुख

देवजी भाई रावत का जम्मू कश्मीर प्रान्त में एक दिवसीय प्रवास हुआ। विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में देवजीभाई रावत ने कहा कि हमें अपने परिवार से ही ऐसे कार्य आरंभ करने चाहिए ताकि बच्चों में इस बात का भेद-भाव ना हो कि वो छोटी या बड़ी जाति के हैं, उन्हें केवल इस प्रकार के संस्कार दें कि हम सब हिन्दू हैं।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रान्त संघचालक ब्रिगेडियर सुचेत सिंह एवं विश्व हिन्दू परिषद् के प्रान्त अध्यक्ष अधिवक्ता लीलाकरण शर्मा ने भी अपने विचार रखे।

भाजपा के एम्एलसी रमेश अरोरा, विहिप प्रान्त कार्य अध्यक्ष सुरेश चंद्र, प्रान्त सामाजिक समरसता प्रमुख पुरुषोत्तम गुप्ता, विहिप उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता, विहिप प्रान्त मंत्री अभिषेक गुप्ता, अजय मन्हास, बजरंग दल के प्रान्त संयोजक नवीन सूदन एवं सभी समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।

rajeshvhp.media@gmail.com



स्वर्गीय डॉ० रमाकांत दुबे को श्रद्धांजलि

जम्मू, 29 मई। विश्व हिन्दू परिषद् के प्रांत संरक्षक स्व० डॉ० रमाकांत दुबे की बरसी के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद् जम्मू-कश्मीर प्रान्त टोली द्वारा विहिप प्रान्त कार्यालय शक्ति आश्रम में श्रद्धांजलि दी गयी। रमाकांत शेष पृष्ठ 21 पर....

महाराणा प्रताप जयंती



जम्मू में 09 मई को धर्म जागरण समन्वय की ओर से वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी जयंती पर बड़ी संख्या में अलग-अलग बिरादरियों के प्रमुख व्यक्तियों ने हिस्सा लिया।

मुख्य वक्ता के रूप में राकेश त्यागी (प्रांत प्रमुख धर्म जागरण) मुख्य अतिथि सरदार बाना सिंह (परमवीर चक्र विजेता) अध्यक्ष संत शर्मा (कैबिनेट मंत्री) विशिष्ट अतिथि डॉ० जितेंद्र सिंह (केन्द्रीय राज्य मंत्री) उपस्थित रहे।

kamalsinghjamwal7@gmail.com



भोपाल क्षेत्र का परिषद शिक्षा वर्ग रायपुर, 28 मई, 2018, rajeshtiwariivhp@gmail.com



कुशी में मंगलवारिया बावडी

कुशी, 24 मई। नगर के समाजसेवियों और युवाओं ने नगर परिषद कर्मचारियों के साथ मिलकर मंगलवारिया स्थित पुरानी पक्की बावडी की सफाई अभियान पत्रिका के अमृत जलम अभियान के अन्तर्गत किया। युवाओं ने कहा कि पत्रिका ही एक ऐसा समाचार पत्र है जो सामाजिक सरोकारों और नवचेतना की बात करता है।

indian.vinay100@gmail.com



1 जून को सूर्यपेट-तेलंगाना में 36 परिवारों के 120 सदस्य अपने पूर्वजों के धर्म में समारोहपूर्वक वापिस आए। विहिप प्रांत मंत्री गाल रेड्डी व प्रांत धर्मप्रसार प्रमुख राजगोपाल नायडू चन्द्रशेखर ने भी सम्बोधित किया। satyam.vhp60@gmail.com

पक्षियों हेतु परिण्डे लगाने का साप्ताहिक अभियान



जोधपुर। राजस्थान की भीषण गर्मी में बेहाल हो रहे पक्षियों की चिंता करते हुए विश्व हिन्दू परिषद जोधपुर महानगर द्वारा सभी प्रखंडों- पक्षियों हेतु परिण्डे लगाने का साप्ताहिक अभियान प्रारंभ किया गया। विहिप ने शहर में 5000 परिण्डे लगाने का निर्णय लिया।

25 मई से 31 मई तक चलने वाले इस अभियान का शुभारंभ पुराना शहर प्रखण्ड संयोजक सुरेंद्र प्रजापत ने करते हुए अपने प्रखण्ड में नई सड़क के आस पास विभिन्न बस्तियों में एक ही दिन में 500 परिण्डे वितरण किये साथ ही 101 किलो पक्षी चुगा भी विभिन्न स्थानों पर वितरण किया।

प्रखण्ड के पिंटू प्रजापत, महेश जलवानिया, प्रियंका बाहेती, भुवनेश खनालिया, शुभम नानेचा, दिव्यांग खिंची, अजय सियोटा, मनीष सेन, सौरभ वर्मा, भटराज राठौड़, मनीष जैन, रोनक सारदा, कृष्णा जाजपुर, मुकेश आदि ने टोलिया बना कर परिण्डे वितरण किये तथा सार्वजनिक स्थान पर परिण्डे लगा कर नियमित पानी भरने का संकल्प लिया। vhpjodhpurmahanagar@gmail.com

एकल की अनूठी पहल

एकल विद्यालय अभियान के तहत पूरे देश के साथ पूर्वोत्तर के दूरदराज इलाके में शिक्षा के साथ बच्चों में संस्कार भरने का प्रेरणादायक कार्य बिना किसी सरकारी मदद की सफलता के साथ चल रहा है। इस पहल से दूरदराज के पिछड़े लोगों के बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार सिखाया जा रहा है। इसकी वजह से विभिन्न जनजातीय समूह अपनी जड़ों की तरफ लौट रहे हैं।

एकल विद्यालय से निकले बच्चे देश के योग्य नागरिक बन रहे हैं। भविष्य में ये बच्चे अपनी संस्कृति के वाहक होंगे लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिना सरकारी मदद के यह अभियान भारतीयता को मजबूत करने वाले लोगों के समूह की तरफ से पूरी निष्ठा से चलाया जा रहा है। विभिन्न व्यवसायों और पेशे से जुड़े लोग अपनी आय का एक हिस्सा इस कार्य के लिए दान देने के साथ अपना समय भी देते हैं। कुछ संस्थाएं भी इस कार्य में सहयोग कर रही हैं।

एकल अभियान से जुड़े कार्यकर्ता पूरी निष्ठा और सादगी से अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि इसके बिना यह अभियान इतनी दूर तक नहीं बढ़ पाता।

बिना किसी सरकारी मदद के एकल विद्यालय अभियान के तहत दूरदराज के इलाके में शिक्षा के साथ संस्कार रोपने की पहल प्रेरणादायक है।

खास बात यह है कि इसके पीछे कोई निजी प्रचार या राजनीतिक लाभ भी नहीं है। इस अभियान से जुड़े या इसमें सहयोग करने वाले लोग बिना किसी प्रचार के राष्ट्र के लिए योग्य नागरिक तैयार कर रहे हैं।

एकल विद्यालय अभियान का सफर पूर्वोत्तर में तेजी से आगे बढ़ रहा है। म्यांमार से सटे मणिपुर के सीमावर्ती इलाके से आगे बढ़ता हुआ महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली बटद्रवा तक पहुंच गया है। जबकि माजुली में इसका कार्य पहले से जारी है और लगातार विद्यालयों की संख्या बढ़ रही है। **बटद्रवा में 30 नए एकल विद्यालयों की स्थापना का दूरगामी प्रभाव दिखेगा।** इस कार्य के लिए मातृ मंदिर का सहयोग अतुलनीय है क्योंकि एकल अभियान सुदूरवर्ती छोटे-छोटे गांव के बच्चों की शिक्षा के कार्य के

माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है।

एकल अभियान के माध्यम से वनवासी समाज को जागरूक किया जा रहा है। एकल अभियान केवल शिक्षा तक ही सीमित नहीं है, यह अभियान गांव के उत्थान और सुरक्षा को सुनिश्चित करने का कार्य कर रहा है। एकल अभियान असम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश तक पहुंच चुका है। **वर्तमान में पूर्वोत्तर में 5580 विद्यालय संचालित हैं। 2019 तक पूर्वोत्तर में विद्यालयों की संख्या 9000 तक पहुंचाने के लक्ष्य पर काम आरंभ हो गया है। निकट भविष्य में 750 नए विद्यालय अन्य स्थानों पर आरंभ होने वाले हैं।** एकल अभियान पूर्वोत्तर की 20 से अधिक जनजातियों को जोड़ चुका है।

इसमें दो राय नहीं है कि एकल अभियान से भारतीयता मजबूत हो रही है। इस अभियान के तहत विभिन्न जनजातियों को एक मंच पर लाया जा रहा है। विभिन्न जनजातीय समूहों के धार्मिक नेताओं के बीच सामूहिक चर्चा भी हो रही है। भले ही उनके विश्वास और प्रतीक अलग-अलग हैं, लेकिन उनके बीच एक सांस्कृतिक और आध्यात्मिक रिश्ता स्थापित करने का प्रयास जारी है। इस कार्य में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ना चाहिए।

(साभार: दै0 पूर्वोदय, गुवाहाटी 1 जून)

पश्चिम बंगाल के पश्चिम मेदिनीपुर – खडगपुर के निकट गोपाली आश्रम में विश्व हिन्दू परिषद् द्वारा अखिल भारतीय सेवा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन २४ मई से २७ मई तक किया गया। इस शिविर में भारत के २६ प्रांतों से ६६ प्रतिनिधि पधारे। केन्द्रीय अधिकारियों में जिनका मार्गदर्शन मिला उनमें प्रमुख थे –

सर्वश्री चम्पत राय, केंद्रीय उपाध्यक्ष, बालष्ण नाईक, केंद्रीय उपाध्यक्ष, मिलिंद परांडे, केंद्रीय महामंत्री, विनायक देशपांडे केंद्रीय संगठन महामंत्री, मधुकर राव दीक्षित, केंद्रीय मंत्री व सह सेवा प्रमुख, नन्द लाल लोहिया, केंद्रीय सह मंत्री व सह सेवा

अखिल भारतीय सेवा प्रशिक्षण शिविर

प्रमुख, आनंद हरबोला, केंद्रीय सह मंत्री व सह सेवा प्रमुख, आनंद प्रकाश गोयल, केंद्रीय सह मंत्री व सह सेवा प्रमुख, सुधांशु पट्टनायक, केंद्रीय मंत्री धर्मप्रसार, प्रमोद कुलकर्णी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ – सेवा दिशा के प्रभारी, श्रीगोपाल झुनझुनवाला, केंद्रीय कोषाध्यक्ष तथा बसंत रथ, केंद्रीय मंत्री सत्संग।

इनके अलावा विभिन्न क्षेत्रों के सेवा प्रमुख सर्वश्री राधेश्याम द्विवेदी, सुधांशु पात्र, हरीश प्रधान, राजेंद्र, संजय कुलकर्णी, भार्गव लक्ष्मण सरपोतदार, रामभाई पटेल भी उपस्थित रहे।

आईआईटी खडगपुर के जिओलॉजी विभाग के प्रमुख प्रोफेसर अनिल गुप्ता ने शिविर का उद्घाटन किया।

विश्व हिन्दू परिषद् के सेवा कार्यो का विवरण ऑनलाइन संग्रह करने की पद्धति की जानकारी के लिए २ सत्र हुए। इसके लिये संघ द्वारा वाट्सअप पर ऑनलाइन विकसित की गयी पद्धति की जानकारी प्रमोद कुलकर्णी ने प्रोजेक्टर के माध्यम से दी।

२६ प्रांतों के लोग अलग-अलग टैबिलों पर अपने लैपटॉप व एंड्राइड

शेष पृष्ठ 23 पर....

उस कट्टर इस्लामी मानसिकता से जनित है, जो गैर-मुस्लिमों के बराबरी के साथ रहने में घृणा और असुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है। इस रुग्ण मानसिकता से आज न केवल भारतीय उपमहाद्वीप, अपितु शेष विश्व भी त्रस्त है। क्या यह सत्य नहीं कि कश्मीर में पथराव करने वाले, आतंकियों की मदद करने वाले और वे जिहादी, जिन्होंने बीते दो दशकों में न्यूयॉर्क में 9/11, मुंबई में 26/11, कई यूरोपीय नगरों और अमेरिकी शहरों में आतंकवाद की पटकथा लिखी—उन सभी को प्रेरणा देने वाला इस्लामी कट्टरवाद का विषैला दर्शनशास्त्र है?

‘काफिर-कुफ्र’ की अवधारणा से संचालित इस दर्शन का मुख्य उद्देश्य—हिंसक जिहाद के मार्ग से ‘दारुल-हरब’

उनकी हिंसक कार्यशैली दिखाई नहीं देती है, उनका विवेक रमजान के दिनों में एकाएक सक्रिय हो जाता है और जिहादी पत्थरबाजों व आतंकियों के विरुद्ध सरकार से नरमी बरतने की मांग प्रारंभ कर देते हैं। क्यों?

देश में इस दोहरे मापदंड की जननी सेकुलरवाद के नाम पर स्थापित वह विकृत विमर्श है, जिसमें पत्थरबाजों और आतंकियों के मददगारों पर सुरक्षाबलों का प्रत्येक प्रतिकार—मानवाधिकारों को कुचलने के सामान हो जाता है और पथराव करने वाले व निरपराधों पर गोली बरसाने वाले जिहादी गुमराह, भटके हुए, गरीब, बेरोजगार और विकास के अभाव से त्रस्त युवा बन जाते हैं, जिसमें सुरक्षाबलों के सभी अधिकार

“भटके” हुए नौजवानों ने 40-50 स्कूली बच्चों से भरी बस पर भी पथराव कर दिया था। अब सभ्य समाज के लिए थिरुमणि और वे स्कूली बच्चे मासूम हैं या फिर “असंतुष्ट” मजहबी उन्मादी?

कश्मीर में भारतीय सुरक्षाबलों का संघर्ष भूमि और लोगों पर नियंत्रण का नहीं है, बल्कि उस दर्शन के खिलाफ है, जो हिंसा के बल पर कश्मीर सहित भारत में बहुलतावाद, लोकतंत्र और मजहबी आजादी को समाप्त करना चाहता है। इसी जिहाद के लिए पाकिस्तान प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार हैं, जो वर्तमान समय में इस्लामी आतंकवाद, कट्टरता और गैर-मुस्लिम विरोधी मानसिकता के बड़े वैश्विक केंद्रों में से एक हैं।

निसंदेह, देश के शेष राज्यों की भांति जम्मू-कश्मीर भी विकास धारा में शामिल हो, उसके नागरिकों को भी सभी मौलिक अधिकार व सुख-सुविधाएं मिलें— किंतु इसका अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं है कि इन सभी के लिए देश की अखंडता, सुरक्षा और संप्रभुता से समझौता कर लिया जाए। यह विचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों और वक्तव्यों से भी स्पष्ट है। आवश्यकता इस बात की है कि कश्मीर सहित देश में उन रुग्ण विचारधारा से संघर्ष किसी भी स्थिति में अविरल रहे, जो विदेशी और भीतरी शक्तियों को बार-बार भारत को खंडित करने हेतु प्रेरित करती है। (26 मई)

— बलबीर पुंज

लेखक पूर्व सांसद तथा दिल्ली स्थित वरिष्ठ पत्रकार हैं।

editorialbp@nayaindia.com

अब यदि कश्मीर में अशिक्षा, गरीबी और बेरोजगारी घाटी में फैले कथित ‘असंतोष’ और ‘भटकाव’ के मुख्य कारण हैं, तो भट जैसे शिक्षित, नौकरीपेशा और आर्थिक रूप से स्वतंत्र युवा-मानवता के शत्रु क्यों बन रहे हैं?

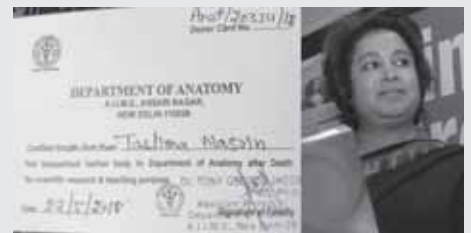
विश्व (भारत सहित) को ‘दारुल-इस्लाम’ में परिवर्तित कर ‘निजाम-ए-मुस्तफा’ को स्थापित करना है। मानवता विरोधी इसी चिंतन ने 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में भारतीय उपमहाद्वीप में मुस्लिम अलगाववाद का बीजारोपण किया, 1946 में बंगाल में “सीधी कार्रवाई” और 1947 में भारत के विभाजन की पटकथा लिखी, 1980-90 के कालखंड में कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न के लिए प्रोत्साहित किया और कालांतर में सैकड़ों इस्लामी आतंकवादी संगठनों को जन्म दिया, जो आज विश्व में वामपंथियों से भी बड़ा खतरा बन चुके हैं।

कश्मीर में विषाक्त इस्लामी चिंतन आज देश की अखंडता, एकता, संप्रभुता, सुरक्षा के लिए चुनौती बने हुए हैं और छद्म-पंथनिरपेक्षता के नाम पर स्थापित विकृत विमर्श ने इसी मानसिकता को हर बार भारतीय बहुलतावाद और सनातनी संस्कृति को चोटिल करने का अवसर दिया है। विडंबना देखिए कि देश में जिन बुद्धिजीवियों (राजनीतिक और सामाजिक) को अक्सर आतंकवादी का मजहब और कट्टर इस्लाम आधारित

(मानवाधिकार सहित) गौण हो जाते हैं। अभी हाल ही में इसी “असंतुष्ट” पत्थरबाजों की फौज ने 7 मई को चेन्नई से श्रीनगर आए पर्यटक आर. थिरुमणि की जान तब ले ली, जब वह श्रीनगर-गुलमर्ग राजमार्ग पर एक वाहन से भ्रमण पर निकला था। हरियाणा से कश्मीर घूमने आया एक युवक भी अनंतनाग से लापता है। इससे पहले, शोपियां जिले के जवूरा क्षेत्र में इन्हीं

देहदानी बनी तस्लीमा

मशहूर बांग्लादेशी लेखिका तस्लीमा नसरीन अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। एक बार फिर वह अपने बयान को लेकर चर्चा में हैं। तस्लीमा ने मौत के बाद अपने शरीर को दफनाने की बजाय एम्स में रिचर्स के लिए दान देने का फैसला किया है। उन्होंने मंगलवार को अपने ट्विटर अकाउंट पर यह जानकारी दी। लेखिका ने अपने ट्वीट में एम्स के डिपार्टमेंट ऑफ एनॉटमी की डॉनर स्लिप भी साझा की। लोगों ने तस्लीमा के इस नेक काम की जमकर तारीफ की और ट्विटर पर जमकर प्रतिक्रिया दी।



www.punjabkesari.in, 22 may



सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र से पूछा, ‘क्या देश के सभी स्कूलों में ‘वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड’ संभव?’

नई दिल्ली, 23 मई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है कि जिसमें देश में वन नेशन-वन एजुकेशन बोर्ड लागू हो सकता है, इस याचिका में कहा गया है कि पूरे देश में एक ही पाठ्यक्रम होना चाहिए।

बीजेपी नेता अश्विनी उपाध्याय की एक याचिका सुनने के लिए सहमति देते हुए न्यायमूर्ति ए. के गोयल और यू. यू. ललित ने केंद्र को इस तरह के सिस्टम को पेश करने की व्यवहार्यता पर अपनी प्रतिक्रिया मांगने के लिए नोटिस जारी किया है। अदालत ने सरकार को प्रतिक्रिया दर्ज करने के लिए आठ सप्ताह का समय दिया है।

शुरुआत में, बेंच को एक बोर्ड के पक्ष में निर्णय लेने के मामले में संदेह था जिसके लिए बेंच अनिच्छुक था। पीठ ने याचिकाकर्ता से कहा, सुनने में यह बहुत ही आकर्षक लग रहा है लेकिन इसे लागू करना आसान बात नहीं है। हमें आदेश पारित नहीं करना चाहिए जिसे लागू नहीं किया जा सका। आपको सरकार से संपर्क करना चाहिए।

याचिकाकर्ता ने जोर देते हुए कहा कि अदालत ने कम से कम सरकार से प्रतिक्रिया मांगी है। इसने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल संदीप सेठी से सभी स्कूलों के लिए एक शिक्षा बोर्ड को कार्यान्वित करने और हासिल करने के तरीके में अदालत की सहायता करने के लिए भी कहा।

मूल्य आधारित सामान्य शिक्षा प्रणाली जिसमें एक सामान्य पाठ्यक्रम शामिल होना चाहिए यह केवल सामाजिक आर्थिक समानता के लिए

आवश्यक नहीं है बल्कि मानवीय एकता और राष्ट्रीय एकीकरण की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए भी आवश्यक है।

कई देशों ने इसे पहले से ही लागू कर दिया है। भारत में भी, न केवल पाठ्यक्रम यहां तक कि सभी स्कूलों और नवोदय विद्यालयों में भी यूनिफार्म भी एक होनी चाहिए। याचिकाकर्ता ने कहा, तमिलनाडु ने इसे पहले से ही लागू कर दिया है।

<https://www.punjabkesari.in>

पृष्ठ 06 का शेषांश....

इस तरह के किसी भी कार्य से पाकिस्तान द्वारा जम्मू-कश्मीर के एक हिस्से पर अवैध कब्जे तथा गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन और शोषण को छिपाया नहीं जा सकता है। साथ ही पाकिस्तान के कब्जे वाले क्षेत्रों के निवासियों को स्वतंत्रता से इंकार नहीं किया जा सकता। इसमें कहा गया है कि इस संबंध में भारत सरकार का स्थायी रुख 1994 में संसद द्वारा सर्वसम्मति से

पारित संकल्प में परिलक्षित होता है।

जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि के बाद संसद ने उस साल फरवरी में संकल्प पारित किया था जिसमें जोर दिया गया था कि राज्य भारत का अभिन्न अंग है और पाकिस्तान को वह हिस्सा खाली करना चाहिए जिस पर उसने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है।

(www.livehindustan.com)

पृष्ठ 11 का शेषांश....

कारण अपना भविष्य मत खराब कर ले। क्योंकि नैतिकता का निर्माण करने वाला समाज प्रत्येक बच्चों के भविष्य को परिवार का ही भावी भविष्य न देखकर, देश का भविष्य मानकर चलता था।

आज की कहानी कुछ और है। लोग अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए ऐसे युवाओं को लालायित भी करते हैं, ऐसे कार्य करने के लिए उकसाते हैं, उन्हें धन मुहैया कराते हैं और फिर उनसे धन वसूलने के लिए उनके परिवार वालों को ब्लैकमेलिंग करते हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा धन वसूला जा सके। चूंकि समाज में अपनी प्रतिष्ठा को बचाके रखना है इसलिए परिवार वाले ऐसे गलत कार्य के लिए धन मुहैया कराने

वाले व्यवसाई को उसके मुंहमांगा धन प्रदान कर देते हैं। दूसरी ओर समाज में ऐसे गलत कार्य करने वाले लोग जो जुआ/सट्टा खिलाते हैं, नशे की चीजें देते हैं इसके बारे में समाज चर्चा तो करता है यह गलत है लेकिन उसका विरोध नहीं करता।

मुझे लगता है आज देश को जरूरत है कि प्रत्येक नागरिक सामाजिक नैतिकता को ध्यान में रखते

हुए हर ऐसे गलत आचरण, गलत कार्य करने वाले और बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध आगे आएँ और जरूरत पडने पर समाज तथा कानून का सहारा लेकर कड़ाई से उसे रोकने में हरसंभव मदद करें।

(23 अप्रैल/18 मई, 2018)

लेखक सामाजिक आर्थिक चिंतन और विश्लेषक बताए जाते हैं।

newpowergame.com

पृष्ठ 17 का शेषांश....

दुबे की बरसी पर शोक प्रकट करते हुए विहिप प्रान्त अध्यक्ष सुरेश जी ने बताया कि डॉ० रमाकांत दुबे देश, समाज एवं भारतीय संस्कृति के विषय में निडरता से देश विरोधी ताकतों का सामना करते थे। इस अवसर पर विहिप

प्रान्त उपाध्यक्ष शक्ति दत्त शर्मा, बाबा यात्री निवास कोषाध्यक्ष बालकृष्ण गुप्ता, मठ- मंदिर विभाग प्रमुख राकेश शर्मा, बजरंग दल प्रान्त संयोजक नवीन सुदन एवं बजरंग दल के कार्यकर्ता उपस्थित थे।

rajeshvhp.media@gmail.com



हल्दीघाटी युद्ध- 18 जून व भामाशाह जयन्ती-28 जून पर विशेष

दानवीरों में श्रेष्ठ भामाशाह

गतांक से आगे.....



के. छगनलाल बोहरा

भामाशाह का सर्वस्व समर्पण

महाराणा प्रताप के आदेश से पूरे युद्धकाल में मेवाड़ में खेतीबाड़ी व्यापार आदि निषिद्ध था ताकि मुगल सेना को किसी प्रकार से रसद प्राप्त न हो सके। ऐसी स्थिति में मेवाड़ के लिए धन जुटाने हेतु भामाशाह ने युक्ति निकाली और मालवा के मुगल इलाकों में धावे मारने निकल पड़े। रामपुरा भाणपुरा, मंदसौर मालपुरा आदि शाही थानों पर धावे कर वहां के जागीरदारों, शाही थानेदारों से दण्ड वसूल कर भारी धनराशि एकत्र की। धनराशि लेकर वे चूलियां ग्राम में महाराणा की सेवा में उपस्थित हुए। अपने पिता और स्वयं द्वारा संचित धन तथा मालवे के शाही इलाकों से वसूला गयी यह सारी धनराशि 25 लाख रूपयें बीस हजार अशर्फियां और अन्य युद्ध सामग्री उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम आगे बढ़ाने हेतु महाराणा को भेंट कर दी।

प्रताप ने भावविभोर हो भामाशाह को गले लगा लिया और कहा कि "स्वतंत्रता संग्राम की इस विकट घड़ी में आपका यह सर्वस्व समर्पण अद्भुत है। आपका यह त्याग और देशहित में सर्वस्व समर्पण विश्व कभी भूलेगा नहीं। आपका यश अमर रहेगा।" और यही वजह है शताब्दियों बाद भी 'भामाशाह' यह शब्द देशहित में धन समर्पण करने वाले दानवीरों के सम्मान का प्रतीक बन गया।

लालचवश स्वामी से गद्दारी करने, आपत्ति काल में धन छुपाने, राजकोष में घोटाले कर धन हड़पने, अमानत में खयानत के अनेक उदाहरण प्रतिदिन सामने आते हैं, ऐसे में समाज के सम्मुख भामाशाह के सर्वस्व समर्पण का प्रेरक उदाहरण विश्व में अद्वितीय है,

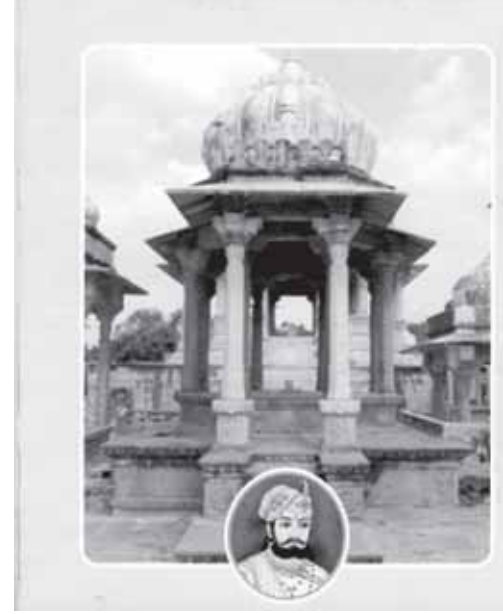
युगों तक नई पीढ़ियों को मार्ग दिखाने वाला है। प्रताप ने भामाशाह का बहुत सम्मान किया, उन्हें उसी वक्त मेवाड़ राज्य का प्रधान अर्थात् महामंत्री नियुक्त किया। प्रताप द्वारा अत्यंत सम्मानपूर्वक दिया गया यह पद वंश परम्परा से भामाशाह के उत्तराधिकारियों के ही पास रहा। इस सम्बन्ध में तत्कालीन कवि द्वारा कहा गया यह दोहा बहुत प्रसिद्ध है "भामो परधानों करे, रामो कीधो रदद। मुगलां बाहर करण नू मिलिया आय मरदद।।"

मुगल पराजय अभियान और भामाशाह की आक्रामक नीति

भामाशाह द्वारा समर्पित धनराशि से सेना और सैन्य सामग्री एकत्रित कर अकबर को खदेड़ने की जो योजना प्रताप ने भामाशाह की सलाह से बनायी उसका प्रारंभ दिवेर से किया गया। अब तक जो रक्षात्मक युद्ध नीति थी, उसके स्थान पर आक्रामक नीति अपना कर अकबर पर आक्रमण करना जिससे दुश्मन स्वयं भयभीत हो भाग जाये।

महाराणा प्रताप, कुंवर अमरसिंह और अनेक वीरों सहित भामाशाह और छोटे भाई ताराचंद स्वयं इस अभियान में शामिल हुए। कुंवर अमरसिंह के भाले के एक ही वार से अकबर का चाचा सुल्तान खां भाले सहित जमीन में गड़ गया। मुगल सेना के अनेक योद्धा प्रताप और भामाशाह के हाथों मारे गये।

भामाशाह और ताराचंद ने युद्ध में अद्भुत पराक्रम दिखाया। शाही सेना अपने सेनापतियों की ऐसी दुर्दशा देख सिर पर पांव रख भाग खड़ी हुई। इस युद्धके समाचार मात्र से अनेक शाही थानों के थानेदार और सैनिक अपनी जान बचाकर अपने थानों का कब्जा छोड़ कर अजमेर की तरफ भाग निकले। प्रताप का यह विजय अभियान भामाशाह के सहयोग से सारे मेवाड़ से मुगल सेना को खदेड़ कर चावण्ड में सुरक्षित राजधानी स्थापित करने तक जारी रहा।



मेवाड़ में एक कहावत बहुत प्रचलित है जिसने इस बात को गलत साबित कर दिया कि राजधानी जीत लिये जाने मात्र से देश जीत लिया गया हो। युद्ध के समय महाराणा राजधानी छोड़कर सुरक्षित पहाड़ों में चले जाते और वहीं से संघर्ष जारी रखते अतः कहावत हो गई कि "जठे राणाजी वठेई उदयपुर।"

मेवाड़ में सुशासन व नवनिर्माण

गहन वन और पर्वत श्रंखलाओं से घिरे शत्रु आक्रमणों से सुरक्षित चावण्ड में प्रताप ने अपनी राजधानी स्थापित की और मेवाड़ के प्रधान महामंत्री के रूप में भामाशाह ने आर्थिक सुदृढ़ता, नवनिर्माण, कृषि का विकास खदानों आदि के कुशल प्रबंधन से राजस्व बढ़ाने की एक सुव्यवस्थित शासन प्रणाली प्रारंभ की। जावरमाता की खदानों से चांदी प्राप्त कर राजकोष को सम्पन्न किया गया। राजपरिवार के लिए महलों व कर्मचारियों के लिए भवनों के निर्माण सहित चावण्डा माता का मंदिर और जैन मंदिरों का निर्माण कराया गया। विद्वानों द्वारा उन्नत कृषि और जल प्रबंधन, ज्योतिष, आयुर्वेद आदि विद्याओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखवाए गये। कला कोशल की उन्नति के लिए कलाकारों को सम्मान और आश्रय दिया गया। चित्रकारी की चावण्ड शैली विकसित हुई।

भामाशाह जैन मतानुयायी थे। प्रताप स्वयं जैन धर्म के प्रति अत्यंत श्रद्धाशील थे। जनता का मनोबल बढ़ाने,

झील किनारे धर्मांतरण करा रहे थे पादरी; अचानक मगरमच्छ निकला और...

झील के किनारे एक पादरी भक्तों की भीड़ के साथ खड़े थे। अचानक पानी से बड़ा सा जीव छलांग लगाकर आया और उन पर टूट पड़ा। पादरी कुछ समझ पाते इससे पहले ही उस जीव ने उन्हें निवाला बना लिया था। असल में वह एक खूंखार मगरमच्छ था। वह इतनी फुर्ती में झील से निकला था कि आसपास खड़े भक्त भी उसके हमला भांप न सके थे। वे भी घटना को लेकर दंग थे।

यह घटना पूर्वी अफ्रीकी देश इथियोपिया की है। रविवार (तीन जून) की सुबह 45 वर्षीय पादरी दोशो एशहेते तकरीबन 80 भक्तों के साथ मर्केब ताबया जिले में अबाया झील पहुंचे थे। वह यहां बपतिस्मा (धर्म परिवर्तन) कराने आए थे। चश्मदीदों के मुताबिक, पादरी एक के बाद एक भक्तों का धार्मिक शुद्धिकरण कर रहे थे, तभी झील से छलांग लगाते हुए एक बड़ा सा मगरमच्छ निकला था। उसने पादरी को बुरी तरह से अपने जबड़ों से जकड़ लिया था।

हालांकि, भीषण हमले के बीच कुछ

मछुआरों ने अपने जाल से मगरमच्छ को काबू कर पादरी की मदद करने की कोशिश की थी। मगर वे पादरी की जान नहीं बचा पाए। दोशो के पैरों, पीठ और हाथों में गंभीर जख्म थे, जिनके कारण मौके पर ही उन्होंने दम तोड़ दिया।

वहीं, पादरी को निवाला बनाने के बाद मगरमच्छ वहां से भाग निकला था। बताया गया कि जिस मगरमच्छ ने पादरी का शिकार किया, वह दुनिया की सबसे लंबी नदी—नील नदी में पाया जाने वाला मगर था। बड़े होने पर उसकी लंबाई 20 फुट तक जा सकती है।



अफ्रीकी महाद्वीप में हर साल नील नदी में पाए जाने वाले मगरमच्छ तकरीबन 300 लोगों को अपना शिकार बनाते हैं। ऐसे में अबाया झील के आसपास आने वालों को अधिक संख्या में पाए जाने वाले मगरमच्छों को लेकर खासतौर पर सावधान रहने की हिदायत दी जाती है।

(जनसत्ता ऑन लाईन, 6 जून)

मोक्ष नगरी काशी में पार्थिव शरीर ले जाने के लिए अब आधार कार्ड जरूरी!

मोक्ष की नगरी काशी में अंतिम संस्कार के लिए मणिकर्णिका और राजा हरिश्चंद्र घाट पर मृतक का आधार कार्ड अनिवार्य किए जाने की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि काशी में

शव वाहिनी (मोटरबोट) सुविधा के लिए अब आधार कार्ड या फिर मृतक से संबंधित कोई भी पहचान पत्र अनिवार्य कर दिया गया है। एनडीआरएफ के सहयोग से यह नई व्यवस्था शुरू की गई है। हालांकि महाश्मशान पर शव जलाने के लिए फिलहाल पहचान पत्र जरूरी नहीं है।

फाउंडेशन की ओर से शवों को महाश्मशान तक लाने के लिए वर्तमान में गंगा में चार स्टीमर 'शव वाहिनी' उपलब्ध कराई गई है। इस व्यवस्था के तहत अब लोग शव लेकर पहले भैंसासुर घाट जाते हैं और वहां से शव वाहिनी से मणिकर्णिका या फिर हरिश्चंद्र घाट पहुंचते हैं। यह व्यवस्था शहर को जाम से निजात दिलाने के लिए की गई है।

(30 मई, नवभाटा)

विकास पाठक, वाराणसी

भेंट की गयी। अत्यंत उत्साह के वातावरण में शिविर का समारोप किया गया।

—नन्द लाल लोहिया
केंद्रीय सहमंत्री व सहसेवा प्रमुख

उनमें सुसंस्कार और अपने धर्म—संस्कृति और मातृभूमि के प्रति समर्पण भाव बढ़ाने के लिए उन्होंने पत्र भेजकर अकबर को सन्मार्ग पर लाने वाले आचार्य हीरविजयजी को मेवाड़ में चातुर्मास हेतु पधारने का निवेदन किया। जैन साधु संत महर्षि धन और सम्मान के प्रति निर्लिप्त होते हैं परन्तु भामाशाह की सलाह पर उनका अनेक प्रकार से सम्मान बढ़ानेवाली राजकीय परंपरा का निवेदन किया। इसी प्रकार जन साधारण में विदेशी विधर्मी आक्रांता मुगलसत्ता के प्रति आक्रोश और निर्भयता का भाव तथा स्वदेश और स्वधर्म के प्रति आत्म गौरव जगाने के लिए आचार्य हेमरतनसूरी को “गौरा बादल री चौपाई” जैसा वीररस का काव्य रचने और उसे जनसाधारण में प्रचारित करने का निवेदन किया।

क्रमशः

पृष्ठ 19 का शेषांश....

मोबाइल पर व्यावहारिक पक्ष से परिचित हुए। प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों के सत्र हुए।

समारोप सत्र में बालकृष्ण नाईक और मधुकर दीक्षित ने मार्गदर्शन किया। इस कार्यक्रम के दौरान ६० विशिष्ट अतिथियों ने परिदर्शन किया। २५ कार्यकर्ता ७ दिनों तक और ४० कार्यकर्ताओं ने २-३ दिनों तक कार्यक्रम को सफल करने में मदद की। गर्मी की अधिकता को दृष्टिगत रखते हुए तदनुरूप भोजन, पेय व जल की व्यवस्था की गई।

केंद्रीय अधिकारियों, प्रतिनिधियों व प्रमुख व्यवस्थापकों को शांतिनिकेतन के झोले, श्री ओंकारेश्वर महादेव को समर्पित रुद्राक्ष की माला व पुस्तकें आदि



वैटिकन की कठपुतली सरकारें लाने को षडयंत्र रच रहा है चर्च : विहिप

नई दिल्ली, 6 जून। चर्च द्वारा वर्तमान सरकारों पर बार-बार हमलों पर अपनी चुप्पी तोड़ विश्व हिंदू परिषद ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि भारत का चर्च, एक बड़े षडयंत्र के तहत, केंद्र व राज्यों में ऐसी सरकारें बनाने में जुट गया है जो कि वैटिकन की कठपुतली बन कर उसका स्वार्थ सिद्ध कर सके। विहिप के संयुक्त महासचिव डॉ. सुरेन्द्र जैन ने कहा कि दिल्ली के आर्कबिशप के बाद अब गोवा के आर्कबिशप को भी संविधान खतरे में दिखाई दे रहा है। अब यह स्पष्ट हो गया है कि वैटिकन के इशारे पर भारत का चर्च वर्तमान सरकारों के विरोध में एक वातावरण बनाने का षडयंत्र कर रहा है। केवल भाजपा सरकार के आने पर ही इनको ऐसा क्यों दिखाई देता है, यह प्रश्न देश पूछना चाहता है। मोदीजी की सरकार के आते ही चर्च पर हमलों के झूठे प्रचार किए गये। और सारे झूठ पकड़े जाने पर भी इन्होंने माफी मांगने की सभ्यता तक नहीं दिखाई। अटल जी की सरकार के समय तो चर्च ने सब सीमाओं को तोड़ दिया था। इसने तत्कालीन सरकार व हिंदू संगठनों पर जिस प्रकार के घिनौने

आरोप लगाए थे, वे किसी सभ्य समाज में चर्चा के लायक भी नहीं हैं। उस समय विहिप ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग से इन आरोपों की जाँच के लिए निवेदन भी किया था। जिस पर आयोग ने भी माना कि ये सभी आरोप झूठे हैं।

डॉ. जैन ने कहा कि वैटिकन सम्पूर्ण विश्व में केवल हिंदू समाज को ही नहीं अपितु, भारत को बदनाम करता है और भारत का चर्च उनकी कठपुतली बनकर अपने ही देश को बदनाम करने का अक्षम्य अपराध करता है। आपात-काल लगाने, कश्मीरी हिंदुओं के नर संहार, 1984 में सिक्खों के कत्लेआम, चकमा बौद्धों पर चर्च के क्रूर जुल्मों से इनको कभी संविधान खतरे में नहीं दिखाई दिया। यह इनका दृष्टिदोष नहीं, वैटिकन के इशारे पर नाचने वाली सरकार को लाने का एक राजनीतिक षडयंत्र है। अर्वाड वापसी माफिया की तरह ये भी एक चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने की सुपारी ले कर काम कर रहे हैं।

विहिप के संयुक्त महा सचिव ने यह भी कहा कि केवल दिल्ली और गोवा के पादरी ही नहीं, मिजोरम, कर्नाटक,

झारखंड, पंजाब आदि राज्यों के चुनावों के समय भी ऐसा ही माहौल बनाकर चर्च ने एक दल विशेष को जिताने के फरमान जारी किए हैं। यह कौन सा सैक्युलर कार्य है? संविधान पूजा का अधिकार देता है परंतु अवैध धर्मांतरण का अधिकार किसी को नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब हिंदुओं के देवी देवताओं का अपमान करना या उनकी मूर्ति जलाना नहीं है। अवैध धर्मान्तरण को रोकने वाले स्वामी लक्ष्मणानंद व शांतिकाली जी महाराज की हत्या कौन से वैधानिक अधिकार के अंतर्गत की जाती है? उन्हें स्मरण रखना चाहिए कि भारत अपने संविधान से चलता है, वैटिकन के मध्ययुगीन बर्बर संविधान से नहीं। भारत के संविधान को चर्च के राजनीतिक व धर्मांतरण के आक्रामक एजेंडे के कारण खतरा है और यह खतरा पूरे देश को भली भांति समझ में आ गया है। इसी एजेंडे के कारण गोवा के आर्कबिशप ने 1947 में भारत की आजादी का विरोध किया था। 1961 में इन्होंने ही गोवा मुक्ति का विरोध करते हुए कहा था कि ईसाइयों का कल्याण पुर्तगाल की गुलामी में ही है। अब उन्हें आत्मविश्लेषण कर अपने पापों के लिए माफी मांगनी चाहिए और वैटिकन से मुक्त होकर भारत के संविधान के अनुसार चलना चाहिए।

प्रस्तुति : विनोद बंसल
(राष्ट्रीय प्रवक्ता, विश्व हिन्दू परिषद)

अयोध्या। विहिप-अंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष चम्पत राय ने राम मंदिर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। कारसेवकपुरम में विहिप के प्रशिक्षण शिविर को संबोधित करने अयोध्या पहुंचे चम्पत राय ने साफतौर पर कहा है कि अभी राम मंदिर को लेकर सरकार कोई कानून न बनाए और जब जरूरत होगी तब विहिप बता देगा।



उन्होंने कहा कि वो राम मंदिर पर कानून बनाने की पेंचीदगियों और परेशानियों से वाकिफ हैं इसलिए इस पर अभी शांत रहने की जरूरत

विहिप उपाध्यक्ष चम्पत राय बोले राम मंदिर को लेकर अभी कोई कानून न बनाए सरकार

है। उन्होंने केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की योगी सरकार को राष्ट्रप्रेमी ताकत बताते हुए कहा कि इनके सत्ता में आने से साधु-संतों और भगवा को आतंकवादी मानना बंद हुआ है वरना साधु-संतों और भगवा को आतंकवादी माना जाता था।

उन्होंने राम मंदिर को लेकर सुप्रीम कोर्ट में लगातार होने वाली सुनवाई का श्रेय भी मोदी और योगी सरकार को देते हुए कहा कि इतिहास इसका श्रेय इन्हीं को देगा और राम जन्म भूमि मामले में

सुप्रीम कोर्ट में त्वरित सुनवाई का श्रेय इतिहास में इन्हीं को जाएगा।

राय का मानना है कि राम मंदिर निर्माण की संभावना जैसे-जैसे बढ़ेगी, वैसे-वैसे अयोध्या में खुद-ब-खुद विकास होगा, क्योंकि राम मंदिर का रास्ता जैसे-जैसे खुलेगा सुगंध फैलती जाएगी और लोग आते जाएंगे और उनके आने के साथ ही अयोध्या में बुनियादी सुविधाओं का विकास होता जाएगा।

(न्यूज18, 7 जून)

डेनमार्क ने सार्वजनिक स्थलों पर बुर्के और नकाब पहनने पर लगाया प्रतिबन्ध



स्टॉकहोम, 1 जून। डेनमार्क की संसद में बुर्के और नकाब को लेकर नया कानून पास हुआ है। अब नए कानून में सार्वजनिक स्थलों पर पूरे चेहरे पर इस्लामी नकाब या बुर्का पहनने पर बैन लगा दिया गया है। चेहरा छिपाने वाले शख्स पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इस कानून को पेश करते समय संसद में मुस्लिम महिलाओं का नाम लिए बगैर कहा गया कि कोई भी नागरिक पब्लिक प्लेस में चेहरा ढंकने वाला कपड़ा पहनेगा तो उस पर 157 डॉलर यानी साढ़े दस हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। बता दें कि इस कानून का सबसे बड़ा नुकसान मुस्लिम महिलाओं को होने वाला है।

संसद ने किया बिल पास.....

डेनमार्क की संसद में इस कानून को 30 के मुकाबले 75 वोट से पास कर दिया। बिल में यह भी कहा गया है कि अगर कोई शख्स कानून को दोबारा तोड़ता है तो उस पर 10 गुना ज्यादा जुर्माना लगाया जाएगा।

इस बिल को डेमोक्रेट्स और

दक्षिणपंथी डेनिश पीपुल्स पार्टी ने अपना सपोर्ट दिया। इसके साथ ही ऐसा कानून बनाने वाला डेनमार्क यूरोपियन यूनियन पर पहला देश भी बन गया है।

यूरोपियन ह्यूमन राइट्स कोर्ट ने पिछले साल पब्लिक प्लेस पर नकाब पहनने पर बेल्जियम में लगाया गया प्रतिबंध बरकरार रखा था। सार्वजनिक

स्थलों पर नकाब पहनने पर रोक लगाने वाला फ्रांस यूरोप का पहला देश था। फ्रांस ने 2011 में ये रोक लगाई थी।

<https://www.bhaskar.com>

30 प्र० में एक से ज्यादा शादी वाले नहीं बन पायेंगे दरोगा; मुसलमानों पर लागू नहीं



अगर आप उत्तर प्रदेश निवासी हैं और दरोगा बनना चाहते हैं तो आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और यूपी कैबिनेट ने इंसपेक्टर और सब इंसपेक्टर नागरिक पुलिस सेवा नियमावली में चतुर्थ संशोधन को मंजूरी

दे दी है। सोमवार (22 मई) को यूपी कैबिनेट की बैठक में 11 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनमें सब इंसपेक्टर और इंसपेक्टर नागरिक पुलिस सेवा नियमावली के चतुर्थ संशोधन को दी गई मंजूरी शामिल है।

नियमावली के नियम 12 और 16 में संशोधन करते हुए यह फैसला किया गया है कि अब एक से ज्यादा शादी करने वाले व्यक्ति को सब इंसपेक्टर और इंसपेक्टर की भर्ती परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह फैसला नियम 12 में संशोधन करके लिया गया है। हालांकि यह फैसला मुसलमानों पर लागू नहीं होगा। इसके साथ ही अब पुलिस विभाग में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग-अलग वैकेंसी नहीं निकाली जाएगी। वहीं नियम 16 में संशोधन करके यह फैसला किया गया है कि अब नियुक्ति प्राधिकारी ही इंसपेक्टर और सब इंसपेक्टर की सीटों का चयन करेंगे।

इसके साथ ही योगी सरकार ने राज्य के मदरसों को लेकर भी अहम फैसला किया है। अब यूपी के मदरसों में विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और कंप्यूटर की पढ़ाई हिंदी और अंग्रेजी माध्यमों में हो सकेगी। यह फैसला भी कैबिनेट की 22 मई को हुई बैठक में लिया गया है।

www.jansatta.com, 23 may

मंदिर में इफ्तार की दावत

रमजान के पवित्र महीने में केरल के मलप्पुरम में स्थित एक मंदिर में इफ्तार का आयोजन किया गया। दावत में 700 मुसलमानों के लिए शाकाहारी भोजन का इंतजाम किया गया था। जिले के कोट्टाकल स्थित भगवान विष्णु के मंदिर में मुस्लिम समुदाय के लिए वेज

बिरयानी और पकवान की व्यवस्था की गई थी। साथ ही फल, जूस और अन्य पेय पदार्थ भी उपलब्ध थे। 'टाइम्स ऑफ इंडिया' के अनुसार, लक्ष्मी नरसिम्हा मूर्ति विष्णु मंदिर में गुरुवार (24 मई) को प्रतिष्ठा दिनम उत्सव मनाया गया, जिसके उपलक्ष्य में विशेष इफ्तार का आयोजन किया गया। मंदिर प्रबंधन समिति ने इसके लिए बकायदा विशेष आयोजन कमेटी का गठन किया था। प्रबंधन समिति के सचिव मोहनन नायर ने बताया कि इफ्तार का आयोजन शांति और समरसता का संदेश देने के लिए किया जाता है।

www.jansatta.com, 24 may



यूरोपीय जर्नल ने माना आयुर्वेद का लोहा

नई दिल्ली, 22 मई। एलोपैथिक दवाओं और उसके दुष्प्रभाव (साइड इफेक्ट) पर शोध करने वाले पश्चिमी देश अब आयुर्वेदिक दवाओं के शरीर पर सकारात्मक प्रभावों को लेकर हैरान हैं। नीदरलैंड के एम्सटर्डम स्थित एलजेवियर ने अपने ताजा अंक में मधुमेह के इलाज के लिए विकसित आयुर्वेदिक दवा बीजीआर-34 पर शोध पत्र प्रकाशित किया है। इसके अनुसार यह दवा मधुमेह को कम करने के साथ-साथ हृदयाघात (हार्टअटैक) को रोकने में मददगार है। लखनऊ स्थित सीएसआइआर की प्रयोगशाला नेशनल बॉटनीकल रिसर्च इंस्टीट्यूट (एनबीआरआई) ने इसे विकसित किया है।

एलजेवियर के जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कंप्लीमेंट्री मेडिसिन में प्रकाशित शोध के अनुसार बीजीआर-34

मधुमेह रोगियों में हार्टअटैक के खतरे को 50 फीसदी तक कम कर देती है। जर्नल के अनुसार भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) की देखरेख में एक अस्पताल में 64 मरीजों पर चार महीने तक इस दवा का परीक्षण किया गया है। इस दौरान दो किस्म के नतीजे सामने आए। यह दवा 80 फीसदी तक मरीजों का शुगर लेवल कम करने में सफल रही और शुगर औसत स्तर 196 (खाली पेट) से घटकर 129 एमजीडीएल रह गया। जबकि भोजन के बाद यह स्तर 276 से घटकर 191 एमजीडीएल रह गया। इसमें हैरानी की बात नहीं है। मधुमेह की दूसरी दवाएं भी इसी तरह शुगर को नियंत्रित करती हैं।

चौंकाने वाली बात दूसरे नतीजे में है। रिपोर्ट के अनुसार इस दवा के उपयोग से 30-50 फीसदी मरीजों में



ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन पूरी तरह नियंत्रित हो गया। जबकि बाकी मरीजों में भी इसके स्तर में दस फीसदी तक की कमी आई थी। ध्यान देने की बात है कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की खून में अधिक मात्रा हार्टअटैक और दौरा पड़ने की प्रमुख वजह है। सामान्य तौर पर मधुमेह रोगियों में ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती है। जर्नल के अनुसार बीजीआर-34 न सिर्फ शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है, बल्कि मधुमेह की बीमारी से जुड़े दूसरे रोगों को ठीक करता है।

— नीलू रंजन

(<https://www.jagran.com>)

डेली हेल्थ पोस्ट की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के Food and Drug Administration ने इस बात की पुष्टि कर दिया है कि चिकन में कैंसर के लिए जिम्मेदार कॉम्पोनेंट आर्सनिक पाया जाता है।

क्या होता है आर्सनिक

आर्सनिक एक फोटो सेंसिटिव मॉलिक्यूल होता है जो कि बॉडी के अंदर कैंसर सेल्स को डेवलप कर देता है। इससे कैंसर सेल्स की ऑटोम्यूटेशन शुरू हो जाती है। जिससे एक बाद चार गुना कैंसर सेल्स बॉडी में बनने लगती हैं। होली के रंग, जंगली घास आदि में ये तत्व पाया जाता है।

WHO की रिपोर्ट के अनुसार आर्सनिक एक नेचुरल कंपोनेंट है जो कि हवा, पानी और लैंड के जरिए डिस्ट्रीब्यूट होता है। यह पानी और फसलों के द्वारा भी बॉडी में पहुंचता है।

बना कैंसर का कारण

अमेरिकन कैंसर सोसायटी ने कई ऐसी एकजाम्पल दिए हैं जिनमें आर्सनिक का

वैज्ञानिकों ने किया बड़ा खुलासा मांस खाने से हो सकता है कैंसर



हाई लेवल बहुत सारे कैंसर का कारण बना है। उन्होंने दो रिपोर्ट्स में आर्सनिक और कैंसर के बीच के संबंध को बताया है। स्टडीज में ऐसे लोगों के बारे में बताया गया है जो पेस्टीसाइड (इनमें

आर्सनिक पाया जाता है) का काम लंबे समय से कर रहे हैं। उन लोगों में लंग कैंसर होने चांजेस ज्यादा पाए गए हैं।

यहां पानी में भी होता है ये मॉलिक्यूल

साउथ अमेरिका और साउथ ईस्ट एशिया की स्टडी के मुताबिक इन देशों में पानी में आर्सनिक बहुत ज्यादा पाया जाता है जो कि ब्लैडर, स्किन और लंग कैंसर का कारण बनता है।

अमेरिकन सोसायटी की जून 2011 की रिपोर्ट के अनुसार आर्सनिक को इसलिए अप्रूव किया गया था क्योंकि ये इन्टेस्टिनल पैरासाइट को मारकर मीट को पिक बनाता है। इसको प्रोड्यूस करने वाले लोगों ने दावा किया था इससे एनिमल खाने वाले लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा?

(www.newspointapp.com, 2 jun)



आगरा



जयपुर

दुर्गावाहिनी शौर्य प्रशिक्षण वर्ग



भोपाल



इटवा



राजनादगाँव (छत्तीसगढ़) में बजरंगदल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग



श्रीराम कथाकार प्रशिक्षण वर्ग



26 मई को जगन्नाथ मठ, हैदराबाद में हरि सत्संग समिति के तत्वावधान में श्रीराम कथाकार प्रशिक्षण वर्ग का समारोह पू. श्रीनिवास व्रत जीयरस्वामी द्वारा प्रदत्त शुभाशीष के साथ किया गया। समारोह सत्र को विहिप के सहमंत्री जी. सत्यम्, प्रांत अध्यक्ष रामराजू समिति की श्रीमती वंदना राठी, श्रीमती जाजू श्रीमती नीता बंसल ने भी सम्बोधित किया। 35 प्रशिक्षुओं ने प्रशिक्षण प्राप्त किया।

गोपाली आश्रम (प.बंगाल) में अ.भा. सेवा प्रशिक्षण शिविर



लुधियाना में कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग



जम्मू में महाराणा प्रताप जयंती



मुंबई में बजरंगदल शौर्य प्रशिक्षण वर्ग

